राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 228 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, बुधवार ,10 फरवरी 2021 , मूल्य रु. 1.50

ममता के नेतृत्व में बंगाल की संस्कृति खतरे में पड़ गई : नड्डा

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में विधानसभा को अभी समय है फिर भी सियासी बयानों के बाण जारी हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के चिल्लर मठ में एक चुनावी सभा करने पहुंचे। इस सभा के दौरान जेपी नड्डा ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा बंगाल में सच में परिवर्तन लाने वाला है। ममता बनर्जी पर हमला करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि वह नहीं चाहती कि बंगाल का विकास हो। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल बदलेगा। वह आएंगे, बार-बार आएंगे और विकास करेंगे।

जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ना तो उनको मां की चिंता है, ना माटी से प्यार है और ना ही मानुष की चिंता है। उनको केवल तानाशाही से मतलब है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया है सिवाय नरेंद्र मोदी की योजनाओं के नाम बदलने के। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान का नाम निर्मल बंगाल, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बंगलर बाड़ी कर दिया गया है। सभा को संबोधित करने के ही दौरान अचानक से जेपी नड्डा की माइक खराब हो गया। इस पर उन्होंने कहा कि मंच बदल सकता है लेकिन इरादे नहीं बदल सकते। भाजपा की परिवर्तन यात्रा बंगाल के घर-घर जाएगी, इलाके का दौरा करेंगे, बंगाल की जनता को जागरूक करेगी और जनता को साथ लेकर बंगाल का असली परिवर्तन करेगी। नड्डा ने दावा किया कि बंगाल में प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है। राजनीति का अपराधिकरण हो गया है। भ्रष्टाचार संस्थागत हो गई है। भाजपा के 130 कार्यकर्ता मारे गए है।

ममता बनर्जी पर हमला जारी रखते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ हम ममता जी और बंगाल को देख रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में बंगाल की संस्कृति खतरे में पड़ गई है। जो बंगाल संस्कृति, विकास, देश दृष्टि और दिशा देने के लिए जाना जाता था, ऐसे बंगाल के विकास को रोकने का काम, बंगाल में भ्रष्टाचार फैलाने का काम, ममता सरकार ने किया है। योजनाएं कितनी भी बनाओ, रोकने की कोशिश करो हम नहीं रुक सकते।

राज्यसभा से विदाई के दिन तारीफ करते भावुक हुए पीएम मोदी

'गुलाम नबी आजाद बेहतरीन मित्र और सहयोगी'

नई दिल्ली, (संवाददाता)। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए भावुक हो गए। पीएम मोदी ने आजाद को एक बेहतरीन मित्र बताते हुए कहा कि सदन के अगले नेता प्रतिपक्ष को आजाद द्वारा स्थापित मानकों को पूरा करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आजाद ने अपने दल की चिंता जिस तरह की, उसी तरह उन्होंने सदन की और देश की भी चिंता की।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के पद पर रहते हुए आजाद ने कभी दबदबा स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा कि आजाद अपनी पार्टी और देश की एक परिवार की तरह चिंता करते हैं, यह कहते हुए पीएम मोदी ने आजाद को सैल्यूट किया। उल्लेखनीय है कि गुलाम नबी आजाद का उच्च सदन में कार्यकाल खत्म हो गया और उन्हें मंगलवार को विदाई दी गई।

प्रधानमंत्री ने बताया कि जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब आजाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। उन दिनों कश्मीर में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ और कुछ पर्यटक मारे गए। इनमें गुजरात के पर्यटक भी थे। मोदी ने कहा तब सबसे पहले, गुलाम नबी आजाद ने फोन कर उन्हें सूचना दी और उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने तत्कालीन रक्षामंत्री प्रणव मुखर्जी से पर्यटकों के पार्थिव शरीर लाने के लिए सेना का हवाई जहाज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। रात को पुनः आजाद ने फोन किया। यह फोन उन्होंने हवाईअड्डे से किया और उनकी चिंता उसी तरह थी जिस तरह लोग अपने परिवार की चिंता करते हैं। यह बोलते हुए प्रधानमंत्री का गला रुंध गया और आंखों में आंसू आ गए।

पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए बहुत भावुक पल था। अगले दिन सुबह पुनः आजाद का फोन आया और उन्होंने पूछा कि मोदी जी, क्या सभी लोग पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि एक मित्र के रूप में घटनाओं और अनुभव को देखते हुए मैं आजाद का बहुत आदर करता हूं। आजाद के बारे में मोदी ने कहा आजाद को सत्ता पक्ष में रहने का और विपक्ष में रहने का लंबा अनुभव है। 28 साल का कार्यकाल बड़ी उपलब्धि होता है। उन्होंने कहा कि बहुत पहले एक बार संसद भवन में लॉबी में वह आजाद से बात कर रहे थे।

मेरा सौभाग्य है मैं भारत में पैदा हुआ : आजाद

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा में कार्यकाल पूरा हो गया है। मंगलवार को सदन में पीएम नरेंद्र मोदी समेत अन्य दलों के नेताओं ने गुलाम नबी आजाद की प्रशंसा करते हुए उन्हें भविष्य के लिए बधाई दी। आजाद ने भी सभी का शुक्रिया अदा करते हुए अपने लंबे राजनीतिक अनुभवों को कुछ किस्सों के जरिए साझा किया। जम्मू रीजन से आने वाले गुलाम नबी आजाद ने बताया कि उन्होंने देशभक्ति महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और मौलाना आजाद को पढ़कर सीखी है। गुलाम नबी आजाद ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और संजय गांधी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया। इसके साथ ही गुलाम नबी ने बताया कि कश्मीर के हालात पहले कैसे हुआ करते थे और अब कितना बदलाव आ गया है। साथ ही पाकिस्तान के बारे में भी अपनी राय रखी। गुलाम नबी आजाद ने सदन में बताया मैं कश्मीर के सबसे बड़े एसपी कॉलेज में पढ़ता था। वहां 14 अगस्त और 15 अगस्त दोनों मनाया जाता था।

आजाद आपको वापस आना होगा, कांग्रेस नहीं लाएगी तो हम लाएंगे : अठावले

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद का उच्च सदन में कार्यकाल मंगलवार को पूरा हो गया है। इस अवसर पर उन्हें राज्यसभा में भावभीनी विदाई दी गई। इसी दौरान आरपीआई के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गुलाम नबी आजाद से कहा कि आप को सदन में फिर से वापस आना चाहिए। अगर कांग्रेस आपको वापस नहीं लाती हैं तो हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं।

केंद्र सरकार ने कार कंपनियों की लगाई फटकार, कहा- कम सुरक्षित वाहन बेचना बंद करें

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने अधिकतर कार कंपनियों द्वारा जानते-बूझते कम सुरक्षित वाहन बेचने पर गहरी नाराजगी जताई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरमाने ने मंगलवार को कहा कि कार कंपनियां व्हीकल सेफ्टी रेटिंग्स सिस्टम नहीं अपना रही हैं। कुछ कंपनियां इन्हें अपना भी रही हैं तो वे कारों के टॉप मॉडल यानी सबसे अच्छे संस्करणों में ही इसका उपयोग करती हैं। बेस या उससे ठीक ऊपर के कई मॉडल में ऐसे इंतजाम नहीं दिखते । यह अक्षम्य अपराध है और कंपनियों को इससे बचना ही होगा।

दूसरे देशों की तुलना में भारत में वाहनों के सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरने संबंधी खबरों पर अरमाने ने कहा कि कंपनियों को इसे गंभीरता से लेना होगा। ऑटो उद्योग की संस्था सियाम के एक कार्यक्रम में उन्होंने ऑटो कंपनियों से दो-टूक कहा कि वे ऐसी कारों बेचना बंद करें, जिनमें सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं।

अरमाने ने कहा कि वर्ष 2018 में अमेरिका में करीब 45 लाख सड़क दुर्घटनाओं में 36,560 यानी एक फीसद से भी कम लोगों की मौत हुई। वहीं भारत में 4.5 लाख दुर्घटनाओं में 1.5 लाख यानी 33 फीसद से अधिक लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में कम मौतों के लिए वाहन सुरक्षा तंत्र का बड़ा योगदान रहा। अरमाने के मुताबिक भारतीय कंपनियां निर्यात होने वाले वाहनों की सुरक्षा गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखती हैं, वहीं देश के भीतर बिकने वाले वाहनों में इसका वैसा ध्यान नहीं रखा जा रहा है। देश के भीतर सिर्फ महंगे वाहनों में सुरक्षा के पर्याप्त उपायों और फीचर पर काम हो रहा है।

सुरक्षा बढ़ाने के लिए नई तकनीक अपनाने पर जोर देते हुए अरमाने ने कहा कि कंपनियों को थ्री-प्वाइंट सीट बेल्ट को भी अपनाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने मौजूदा दौर में सीट बेल्ट व एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का भी जिक्र किया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग (वीएलटी) प्रणाली को भी उन्होंने एक अहम कदम बताया। वीएलटी व सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल बीमा कंपनियों के द्वारा भी किया जाने लगा है। जीपीएस प्रणाली की शुरुआत को एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए अरमाने ने कहा कि इससे सुरक्षा मिलने के साथ-साथ टोल कलेक्शन का काम भी आसान हो जाएगा। जीपीएस सिस्टम को सभी वाहनों में लगाने की बात चल रही है।

वाहन डीलरों की संस्था फाडा ने मंगलवार को बताया कि जनवरी, 2021 में सालभर पहले की समान अवधि की तुलना में यात्री वाहनों की बिक्री करीब चार प्रतिशत गिरी है। आंकड़ों के मुताबिक, समीक्षाधीन महीने में इनकी संख्या घटकर 2,81,666 रही। फाडा ने बताया कि इसमें सेमीकंडक्टर की कमी सबसे बड़ी वजह बनी। एक साल पहले की तुलना में पिछले महीने दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी 8.78 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री भी कम हुई है।

दिल्ली में जर्जर मकान ढहा, पांच लोगों को मलबे से निकाला तीन की हालत नाजुक

नई दिल्ली, (संवाददाता)। उत्तरी दिल्ली के सदर बाजार इलाके में मंगलवार की सुबह एक घर ढह गया। इस हादसे के बाद दमकल कर्मियों ने मलबे से पांच लोगों को बाहर निकाला। मकान में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आंशका है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि घर ढहने की सूचना पूर्वाह्न लगभग साढ़े दस बजे मिली और दमकल की छह गाड़ियो को मौके पर भेजा गया।

उन्होंने बताया कि अब तक पांच लोगों को बचाया गया है, जिनमें से तीन की हालत नाजुक है। उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान जारी है। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार सुबह 10:30 हमें सूचना मिली की सदर बाजार में कुरैशी नगर इलाके के गली चरखे वाली का एक घर ढह गया। इसके तुरंत बाद फायर टेंडर की 6 वाहनों को राहत एवं बचाव के लिए मौके पर भेजा गया जहां पर उन्होंने मलबे में दबे पांच लोगों को बाहर निकाल लिया। मकान गिरने की वजह फिलहाल पता नहीं चली है।

मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठा जवाहरलाल नेहरु और राजीव गांधी बैठे : शाह

नई दिल्ली, (संवाददाता)। लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृहमंत्री शाह पर रवींद्रनाथ टैगोर का अपमान करने का आरोप लगाया। जिसका गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देकर कहा कि अधीर रंजन जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जब मैं विश्वभारती और शांति निकेतन में गया,तब गुरुदेव टैगोर की कुर्सी पर बैठा। मेरे पास विश्वभारती के उपकुलपति का पत्र है जिसमें मैंने स्पष्टता मांगी है कि सभी चीज की जांच करके बताइए कि कहां पर मैं बैठा हूं।

गृह मंत्री ने बताया उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। जहां पर मेरे बैठने का जिक्र है, वहां एक खिड़की है, जहां सभी के बैठने की व्यवस्था है। उसी स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति भी बैठीं थीं, प्रणब दा भी बैठे थे, राजीव गांधी भी बैठे थे, मैं भी वहीं बैठा हूं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब आईं तब उन्होंने स्मरिका के अंदर उसी स्थान पर बैठकर अपनी टिप्पणियां लिखी। मेरा इतना ही कहना है कि इस सदन में जब कभी हम बात करते हैं तब बात करने से पहले तथ्यों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। अगर हम सोशल मीडिया से उठाकर हम यहां में रख दें,तब इस सदन की गरिमा को क्षति पहुंचती है।

उन्होंने कहा कि मैं तो उस कुर्सी पर नहीं बैठा, लेकिन मेरे पास दो फोटो हैं, जिसमें एक पर जवाहरलाल नेहरु उस कुर्सी पर बैठे दिख रहे हैं। दूसरी फोटो में राजीव गांधी टैगोर साहब के सोफे पर बैठकर चाय पीते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो इस सदन में उपस्थित नहीं होता है उसके नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा जी के नाम का भी उल्लेख किया है। मैंने नड्डा जी के भाषण को पूरा सुना है। मैं चैलेंज करता हूं कि नड्डा जी ऐसा बोले हैं,तब उसे रिकॉर्ड पर रखें।

बंगाल चुनाव में फर्जी वोटरों पर नकेल कसने की तैयारी

चुनाव आयोग कर सकता है ईसीआई एप का इस्तेमाल

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में फर्जी मतदाताओं की पहचान करने एवं चुनाव प्रक्रिया के ब्यौरे तत्काल सामने लाने के लिए निर्वाचन आयोग अपने बूथ मोबाइल ऐप का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। यह जानकारी एक अधिकारी ने मंगलवार को दी। अगर ऐसा होता है, तो पश्चिम बंगाल पहला राज्य होगा, जहां की चुनावी प्रक्रिया में इस ऐप का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा।

निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने बताया कि यह अभी योजना के स्तर पर है। अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया हैं। हमें उम्मीद है कि इससे पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि ऐप निर्वाचन आयोग के सर्वर से जुड़ा है एवं कूट (इनक्रिप्टेड) तरीके से आंकड़े देगा। अधिकारी ने बताया कि यह लिंग एवं आयु आधारित मतदान की जानकारी देता है। यह मतदान की गति और चुनाव संबंधी अन्य जानकारी भी देता है।

फोटो मतदाता पर्ची पर होगा कूटबद्ध क्यूआर कोड : उन्होंने बताया कि फोटो मतदाता पर्ची पर कूटबद्ध क्यूआर कोड होगा, जिसे मतदाता को मतदान केंद्र में प्रवेश देने से पहले स्कैन किया जाएगा। मतदान करने से पहले इस कोड को दूसरी बार स्कैन किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि जैसे ही मतदाता मतदान करेगा, उसका डाटा निर्वाचन आयोग के सर्वर पर चला जाएगा, जिससे पीठासीन अधिकारी वास्तविक समय में मतदान प्रतिशत एवं अन्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे चुनाव प्रक्रिया को न केवल गति मिलेगी, बल्कि सही जानकारी दर्ज हो यह सुनिश्चित होगा।

चुनाव अधिकारियों के फोन में तेज आवाज करके करेगा आगाह : अधिकारी ने बताया कि बूथ ऐप मतदान के दोहराव का पता लगाने में सक्षम है और ऐसा होने पर वह चुनाव अधिकारियों के फोन में तेज आवाज करके उन्हें आगाह कर देगा। उन्होंने बताया कि इस ऐप का इस्तेमाल प्रायोगिक तौर पर वर्ष 2019 के चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के पांच, महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब के तीन बूथों एवं झारखंड की 10 सीटों पर किया गया था। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव इस साल अप्रैल-मई में होने हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने छह समुदायों को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मामले में केंद्र सरकार को दिया नोटिस

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने छह समुदायों को अल्पसंख्यक दर्जा देने की अधिसूचना और अल्पसंख्यक आयोग की वैधानिकता को चुनौती देने वाली विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित करने की मांग पर मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। भाजपा नेता और वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण याचिका दाखिल कर दिल्ली, गुवाहाटी और मेघालय उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित कर एक साथ सुनवाई करने की मांग की है, ताकि एक ही मुद्दे पर भिन्न फैसले आने की संभावना न रहे।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्थानांतरण याचिका पर बहस सुनने के बाद गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने इस स्थानांतरण याचिका को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान कानून को चुनौती देने वाली पहले से लंबित याचिका के साथ सुनवाई के लिए संलग्न करने का आदेश दिया है। उपाध्याय ने स्थानांतरण याचिका में कहा है कि अल्पसंख्यक आयोग कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। अल्पसंख्यक आयोग शिक्षण संस्थान को चुनौती देने वाली याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को भी सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करके एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए।

स्थानांतरण याचिका में कई समुदायों को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि लद्दाख में रहने वाले एक फीसद हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं है जबकि 46 फीसद मुसलमान और 50 फीसद बौद्ध को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है। इसी तरह मिजोरम में हिंदू मात्र 2.75 फीसद, लक्षद्वीप में 2.77 फीसद, कश्मीर में 4 फीसद, नगालैंड में 8.74 फीसद, मेघालय में 11.52 फीसद हैं। लेकिन उन्हें अल्पसंख्यक दर्जा नहीं मिला है, जबकि मिजोरम के 88 फीसद ईसाई, लक्षद्वीप के 96.58 फीसद मुस्लिम, कश्मीर के 95.5 फीसद मुस्लिम, नगालैंड के 88.1 फीसद ईसाई, मेघालय के 75 फीसद ईसाई को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है।

उपाध्याय ने कहा है कि यहूदी, बहाई जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक जिनकी संख्या बहुत कम है, उन्हें न राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है और न केंद्रीय स्तर पर। इसलिए 1993 की अल्पसंख्यक दर्जा देने वाली अधिसूचना असंवैधानिक है। 1993 की अधिसूचना में पांच समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था, जिसमें 2014 में जैन को भी जोड़ दिया गया। कहा गया है कि 2002 में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की पीठ ने टीएमए पाई फैसले में स्पष्ट कर दिया था कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की पहचान राज्यवार होगी न कि राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन अभी तक वह फैसला लागू नहीं हुआ। याचिका में वैकल्पिक मांग है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की राज्यवार पहचान की जाए।

के 2 पर फतह की कोशिश में पाकिस्तान के तीन पर्वतारोही लापता, सेना ने रेस्क्यू का काम रोका

इस्लामाबाद। दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर के 2 पर गए तीन पर्वतारोहियों की तलाश का काम पाकिस्तानी सेना ने रोक दिया है। लापता हुए तीन पर्वतारोहियों में पाकिस्तान के प्रख्यात पर्वतारोही मुहम्मद अली सादपारा भी शामिल हैं। सादपारा और दो अन्य पर्वतारोही- जॉन नूरी (आइसलैंड) व जुआन पाब्लो (चिली) 8,611 मीटर ऊंचे के 2 शिखर पर पहुंचने की

कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान वे लापता हो गए।

अगले दिन सेना के दो हेलीकॉप्टर पर्वतारोहियों की तलाश में भेजे गए लेकिन दो दिन की मशक्कत के बाद ये हेलीकॉप्टर लापता लोगों की तलाश नहीं कर पाए। दोनों हेलीकॉप्टरों ने अधिकतम 7,800 मीटर की ऊंचाई तक जाकर पर्वतारोहियों की तलाश की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। पाकिस्तान के एल्पाइन क्लब के अधिकारी करार हैदरी ने कहा है कि सादपारा, नूरी और पाब्लो की सलामती के लिए दुआ मांगी जा रही है। इस बीच सादकारा का बेटा साजिद के 2 के रास्ते से लौटकर स्कार्दू पहुंच गया है। साजिद की ऑक्सीजन किट में खराबी आ गई थी, इसके कारण उसे बीच से ही वापस लौटना पड़ा।

साजिद ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि अत्यंत ठंडे मौसम में तीनों पर्वतारोहियों के सही-सलामत होने की संभावना बहुत कम है। उन्होंने यह भी कहा कि पर्वतारोहियों के शवों को ढूंढ़कर लाने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। के 2 पर चढ़ने की कोशिश में ही बल्गारिया के पर्वतारोही एटनास स्कातोव की मौत हुई थी। सादपारा पाकिस्तान के प्रख्यात पर्वतारोही हैं। उन्होंने आठ पर्वत चोटियों पर पाकिस्तान का झंडा फहराया है। वह 2016 में नंगा पर्वत पर विजय प्राप्त करने वाले दल में भी शामिल थे। नंगा पर्वत पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। वहां जाने की कोशिश करने वाले तमाम लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है।

अंतरिक्ष में फिर एक बार बढ़ेगी चहलकदमी, दस दिन में मंगल पर पहुंचेंगे तीन अंतरिक्ष यान

केप केनेवेरल। लाखों मील दूर अंतरिक्ष में एक बार फिर चहलकदमी बढ़नेवाली है जब तीन अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर उतरेंगे। इनमें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का यान तो मंगलवार को पहुंचेगा। इसके 24 घंटे बाद चीन का आर्बिटर रोवर कोंबो मंगल की यात्रा करेगा। इन दोनों देशों के यान के एक सप्ताह बाद नासा का रोवर कॉस्मिक कैबूज 18 फरवरी को मंगल पर कदम रखनेवाला है। वह वहां मिट्टी तथा मौजूद चट्टानों के टुकड़े एकत्र करेगा और फिर उन्हें लेकर धरती पर वापस लौटेगा। अंतरिक्ष के इन अभियानों का उद्देश्य इस बात का पता लगाना है कि क्या मंगल में कभी जीवन था।

मंगल की यात्रा करने के प्रयास में संयुक्त अरब अमीरात और चीन नए देश हैं। इनके बहुत सारे अभियान असफल रहे हैं। रूस के सहयोग से वर्ष 2011 में चीन ने पहली बार मंगल पहुंचने की कोशिश की थी। उधर यूएई के विज्ञानी अपने इस मिशन को लेकर बेहद उत्साहित हैं। यूएई मंगल अभियान के प्रोजेक्ट मैनेजर ओमरान शराफ ने कहा कि हम खुश हैं, पर चिंतित और तनाव में भी हैं।

ट्रंप के खिलाफ महाभियोग ट्रायल को तेजी से चाहते हैं अमेरिकी सीनेट

वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ऐतिहासिक दूसरे महाभियोग ट्रायल की ओर हैं, इसमें सीनेटर चाहते हैं कि इसे जल्दी से किया जाए। ट्रायल के दौरान सीनेट को यह फैसला करना है कि 6 जनवरी को यूएस कैपिटल की घेराबंदी करने के लिए ट्रंप को उनके समर्थकों की हिंसक भीड़ को उकसाने का दोषी ठहराया जाए या नहीं।

द हिल ने बताया, सीनेट के प्रमुख नेता चार्ल्स शूमर और अल्पसंख्यक नेता मिच मैककोनेल अभी भी ट्रायल को लेकर संगठन से एक डील चाहते हैं। सीनेटर केविन क्रैमर ने कहा, %मैं कल्पना नहीं कर सकता कि यह एक सप्ताह से आगे बढ़ने वाला है ... मुझे नहीं लगता कि इस चीज के लिए किसी में बहुत उत्साह है। सीनेटर जॉन थुन(नंबर दो सीनेट रिपब्लिकन) ने द हिल को बताया कि दोनों पक्षों को एक छोटे ट्रायल की जरूरत नजर आ रही है। इस बड़ा नहीं होना चाहिए। यह तर्क देते हुए कि ट्रंप का महाभियोग ट्रायल आवश्यक है, सीनेट डेमोक्रेट ने राष्ट्रपति जो बाइडन के कोविड-19 राहत पैकेज पर ध्यान केंद्रित कर किया। सीनेटर रिचर्ड ब्लूशहाल ने सी.एन.एन. को कहा, यह एक छोटा ट्रायल होगा। इसमें कुछ भी छुपाना जैसा नहीं है, यह खुला है, जिसमें ट्रंप ने अपने ट्वीट में कैपिटल में आने के लिए अपने लोगों को कहा था। एक वरिष्ठ जीओपी सीनेटर ने बताया कि उन्हें लगता है कि ट्रायल शुक्रवार या शनिवार को जल्द से जल्द निपट सकता है, क्योंकि यही दोनों पक्ष शायद करना चाहते हैं।

म्यांमार में तख्ता पलट का विरोध

यांगोन में 30 हजार से ज्यादा लोगों का प्रदर्शन

'सू की को मां कहा, लंबी उम्र के नारे लगाए'

यांगून। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये प्रदर्शनकारी देश की शीर्ष नेता आंग सान सू की रिहाई की मांग कर रहे हैं।

इस क्रम में म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगोन में सेना के खिलाफ जनसैलाब उमड़ पड़ा। यांगून यूनिवर्सिटी के पास करीब 30 हजार से ज्यादा लोग जुटे और प्रदर्शन किया।

इस दौरान लोगों ने 'आपकी उम्र लंबी हो मां सू' और 'सैन्य तानाशाही खत्म करो...' जैसे नारे लगाए। लोगों ने मुख्य सड़क की ओर मार्च किया। इससे यातायात प्रभावित हुआ। वहीं, वाहन चालकों ने भी हॉर्न बजाकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया।

रिपोर्ट के मुताबिक, सेना ने फेसबुक और ट्विटर जैसे इंटरनेट

मीडिया प्लेटफॉर्म को अवरुद्ध करने का आदेश दिया था। लेकिन देश के कुछ हिस्सों में यह आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया। इंटरनेट शटडाउन पर नजर रखने वाली लंदन स्थित कंपनी नेटब्लॉक् ने रविवार को इंटरनेट कनेक्टिविटी की आंशिक बहाली की पुष्टि की।

यूएन मानवाधिकार परिषद की ओर बाइडन प्रशासन

ट्रंप की विदेशी नीतियों में एक और बदलाव

वाशिंगटन। अमेरिका में बाइडन प्रशासन द्वारा इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के साथ फिर से जुड़ने की घोषणा करने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीन वर्ष पहले परिषद से अमेरिका को अलग करने का फैसला लिया था। यह जानकारी अमेरिका के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दरअसल, बाइडन प्रशासन के इस फैसले से बहुपक्षीय संगठनों और समझौतों के संबंध में पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन द्वारा लिया गया एक और निर्णय पलट जाएगा।

अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बाइडन प्रशासन का मानना है कि परिषद में सुधारों की आवश्यकता है लेकिन परिवर्तन लाने का सही तरीका है %उसके साथ मिलकर सैद्धांतिक तरीके से काम करना।

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन

और जेनेवा में अमेरिका के वरिष्ठ राजयनिक इस बाबत सोमवार को घोषणा करेंगे। बता दें कि वर्ष 2018 में ट्रंप ने ह्र मानवाधिकार परिषद से अलग होने का फैसला लिया था। उन्होंने इजरायल के प्रति परिषद के रुख व इसके सदस्यों के संबंध में ऐतराज जताया था।

ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका द्वारा बताए गए सुधार करने में भी परिषद विफल रही है। ट्रंप प्रशासन को परिषद के सदस्यों-चीन, क्यूबा, इरीट्रिया, रूस और वेनेजुएला को लेकर आपत्ति थी, जिन पर मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगते रहे हैं।

ड्रैगन की घटिया चाल का खुलासा: चीन ने नेपाल पर वैक्सीन लेने के लिए दबाव डाला, चीनी एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स लीक

काठमांडू। महामारी के दौर में भी चीन छोटे और गरीब देशों को धमका रहा है। इसका एक और उदाहरण सामने आया। दरअसल, नेपाल के मीडिया ने कुछ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताया है कि चीन ने नेपाल सरकार पर सायनोवैक वैक्सीन को खरीदने के लिए दबाव बनाया था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, यह दबाव तब से बनाया जा रहा था जब चीन की वैक्सीन्स का एफिशिएन्सी डेटा भी मौजूद नहीं था और न ही इनकी पुष्टि हुई थी।

चीन के विदेश मंत्री ने किया था फोन

न्यूज एजेंसी ने नेपाली मीडिया के हवाले से इस पूरे मामले का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की सायनोफार्म कंपनी सायनोवैक कोविड-19 वैक्सीन बना रही है। इसकी एफिशिएन्सी पर सवालिया निशान लगते रहे हैं। शुक्रवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप जवाली को फोन किया। उन्होंने प्रदीप पर दबाव बनाया कि वे चीन की वैक्सीन को मंजूरी दें। खास बात ये है कि वांग यी ने

पहले मंजूरी मांगी और साथ ही ये भी कहा कि वैक्सीन की डीटेल्स बाद में दी जाएंगी।

नहीं तो वैक्सीन के लिए इंतजार करना होगा

काठमांडू में चीन की एम्बेसी पर नेपाल की राजनीति में दखलंदाजी के आरोप लगते रहे हैं। अब वैक्सीन के मामले में तो इसी एम्बेसी के दस्तावेज लीक हो गए हैं। एक डॉक्यूमेंट में तो नेपाल सरकार को धमकी दी गई है कि अगर उसने वैक्सीन को मंजूरी देने में देरी की तो फिर नेपाल को इसके लिए लंबा इंतजार करना होगा।

नेपाल ने कहा- दस्तावेज सही

रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल सरकार ने लीक हुए दस्तावेजों की पुष्टि करते हुए इन्हें सही बताया है। दूसरी तरफ, चीन की एम्बेसी ने इस मामले में कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। नेपाल ही नहीं, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों में चीन की वैक्सीन्स पर सवालिया निशान लग रहे हैं।

यह मामला इसलिए भी उलझ रहा है क्योंकि नेपाल सरकार ने पिछले हफ्ते गुरुवार को चीन सरकार को एक लेटर के जरिए बताया था कि कोई भी चीनी वैक्सीन कंपनी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डेटा नहीं दे रही है। 31 जनवरी को चीनी दूतावास ने कहा था कि वो नेपाल को सायनोवैक वैक्सीन के 3 लाख डोज मुहैया कराएगी। भारत और ब्रिटेन नेपाल को 2-2 लाख वैक्सीन पहले ही भेज चुके हैं। ब्राजील में सायनोवैक वैक्सीन की एफिशिएन्सी सिर्फ 50.4फीसदी आंकी गई थी। इसके बाद वहां इसके ट्रायल ही बंद कर दिए गए थे।

ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोरोना वायरस के नए प्रकार के खिलाफ भी प्रभावी

लंदन। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित और एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित कोरोना वैक्सीन ब्रिटेन में सामने आए वायरस के नए प्रकार के खिलाफ भी प्रभावशाली दिखा है। यह जानकारी अनुसंधानकर्ताओं की ओर से किए जा रहे अध्ययन से सामने आई है।

सीएचएडीओएक्स1-एनसीओवी19 टीका विकसित करने वाले विज्ञानियों ने पाया है कि यह बीमारी के कम से कम एक नए प्रकार के खिलाफ प्रभावी है, जिसे बी.1.1.7 'केंट' कहा जाता है। इस नए प्रकार का पता पहली बार पिछले साल के अंत में दक्षिण-पूर्व ब्रिटेन में चला था। ऑक्सफोर्ड टीके के परीक्षण संबंधी मुख्य जांचकर्ता एवं बच्चों के संक्रमण एवं प्रतिरक्षण के प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने कहा, ब्रिटेन में सीएचएडीओएक्स1 टीके के हमारे परीक्षण डाटा से संकेत मिलता है कि यह न केवल मूल

वायरस से बचाता है, बल्कि इसके नए स्वरूप के खिलाफ भी कारगर है। हालांकि, एस्ट्राजेनेका ने कहा कि यह अभी तक पूरी तरह से निर्धारित किया जाना बाकी है कि क्या यह टीका दक्षिण अफ्रीका में सामने आए अत्यधिक संक्रामक कोरोना वायरस से भी बचाता है। दरअसल प्रकाशन से पूर्व अध्ययन के एक छोटे हिस्से के हवाले से कंपनी ने विश्वास जताया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ यह वैक्सीन गंभीर मामलों से सुरक्षा प्रदान करेगी, क्योंकि इसने अन्य कोरोना वायरस के टीकों के समान ही बेअसर करने वाले एंटीबॉडी बनाए हैं।

वायरस से जुड़े मामलों में अभी भी झूठ बोल रहा चीन, सही आंकड़े पता करना कठिन

वाशिंगटन। भले ही चीन में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई हो, लेकिन विशेषज्ञ अभी भी उस पर वायरस से जुड़े मामलों में झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने कुछ दिनों पहले दुनियाभर में कोरोना के प्रसार के लिए ना केवल बीजिंग को जवाबदेह ठहराया था बल्कि यह भी कहा था कि वायरस से संबंधित जानकारी पर उसे पारदर्शी रवैया अपनाना चाहिए।

यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर का हवाला देते हुए कहा कि चीन अभी भी महामारी मरीजों की संख्या के बारे में झूठ बोल रहा है। प्रोफेसर स्टेनली रोसेन ने फॉक्स न्यूज को ई-मेल के माध्यम से बताया, आंकड़ों में अशुद्धि की सबसे बड़ी वजह स्थानीय अधिकारी हैं जो केंद्र सरकार को डाटा उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने कहा कि आंकड़ें भले ही पूरी तरह से ठीक नहीं हों, लेकिन महामारी को रोकने के लिए चीन अच्छा काम कर रहा है। चीनी राजनीति के विशेषज्ञ रोसेन ने कहा कि बिना लक्षणों वाले मरीजों को संक्रमित मरीजों में शामिल नहीं किया जा रहा है। हालांकि ऐसे मरीजों की संख्या बहुत कम है। उन्होंने कहा, जब पारदर्शिता की

बात आती है तो चीन का रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना होता है। ऐसे में यह जानना बहुत कठिन है कि उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, वह कहां तक सही हैं। वाशिंगटन विश्वविद्यालय के महामारी विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉ. स्टीफन ई हाविस ने कहा कि चीन ने ना केवल महामारी की जानकारी छिपाई बल्कि देश के अंदर महामारी को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

पाकिस्तान में एक और सर्जिकल स्ट्राइक, ईरान ने अंदर घुसकर छुड़ाए अपने दो सैनिक

ईरान। पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। भारत की तर्ज पर इस बार पाकिस्तान को घर में घुसकर ईरान ने सबक सिखाया है। ईरान की सेना का हिस्सा रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर अपने दो सैनिकों को छुड़ा लिया है, जिन्हें आतंकियों ने बंधक बना लिया गया था।

इन सैनिकों को करीब ढाई साल पहले जैश उल-अदल संगठन ने बंधक बनाया था। ईरान ने पाकिस्तान सरकार और सैना से लगातार सम्पर्क बनाए रखा, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला तो बीते मंगलवार को इस सर्जिकल स्ट्राइक को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अब दोनों सैनिकों को सुरक्षित ईरान में भेज दिया गया है।

बता दें, जैश उल-अदल एक आतंकवादी संगठन है, जिसने पाकिस्तान में गहरी जड़े जमा ली हैं। इस कट्टरपंथी वहाबी संगठन ने 16 अक्टूबर, 2018 को दोनों देशों की सीमा पर बलूचिस्तान प्रांत के मर्कवा शहर में ईरान की सेना के 12 सैनिकों का अपहरण कर लिया था। जिस समय अपहरण हुआ, तब ये सैनिक पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच चली कूटनीतिक वार्ता के परिणाम स्वरूप दो टुकड़ों में 10 सैनिकों को छुड़ा लिया गया था, लेकिन आतंकवादी संगठन ने 2 सैनिकों को अब तक अपने कब्जे में रखा था।

चेहरा दुनिया के सामने ला दिया था। अब एक बार फिर साबित हो गया कि पाकिस्तान में डेरा जमाए बैठे आतंकी संगठन बेकाबू होते जा रहे हैं। जैश उल-अदल के बारे में कहा जाता है कि इस संगठन ने ईरान में कई सैन्य ठिकानों

पाकिस्तान सरकार ने साधी चुप्पी

इस सर्जिकल स्ट्राइक की खबर सामने आने के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। भारत ने सफल सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान का असली के साथ ही नागरिकों पर भी हमले किए हैं। पाकिस्तान की ओर से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर जरूर पड़ेगा।

अमेरिका में टीकाकरण का विरोध: कैलिफोर्निया राज्य में कोरोना से रोज 500 मौतें हो रहीं, यहां भी वैक्सीन के विरोध में प्रदर्शन

कैलिफोर्निया । महामारी के दौरान महीनों तक मास्क और लॉकडाउन के खिलाफ रैली करने वाले कुछ प्रदर्शनकारी अब कोविड -19 वैक्सीनेशन के विरोध में खड़े हो गए हैं। हाल ही में कुछ लोगों ने कोरोना वायरस वैक्सीन के विरोध में डोजर स्टेडियम में सामूहिक टीकाकरण स्थल के एंट्री गेट पर धावा बोल दिया।

कैलिफोर्निया वैक्सीन के विरोध का पुराना अप्रिय केंद्र रहा है, जबकि इधर कोरोनावायरस राज्य में अभी भी फैल रहा है। पिछले हफ्ते कैलिफोर्निया में हर रोज औसतन 500 लोगों की मौत कोरोना से हुई और जल्द ही यह न्यूयॉर्क को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा मौतों वाला राज्य बन जाएगा।

विरोध का नया तरीका

महीनों से ये कट्टर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता मास्क पहनने के नियमों, बिजनेस लॉकडाउन, कर्फ्यू और स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ रैली कर रहे हैं। वे इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सरकार का हस्तक्षेप बताते रहे हैं। लेकिन अब जब मास्क और लॉकडाउन अमेरिकी जीवन हिस्सा बन गए हैं, तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध और गुस्सा कोविड-19 के टीकों की ओर मोड़ दिया है।

पिछले सप्ताह इन प्रदर्शनकारियों के एक छोटे ग्रुप ने डोजर स्टेडियम के टीकाकरण स्थल पर हंगामा खड़ा कर दिया। स्टेडियम के प्रवेश को बाधित करने की कोशिश की गई। इस स्टेडियम में रोजाना औसत 6,120 लोगों को टीका लगाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने 'डोंट बी लैब रैट' और 'कोविड-स्कैम' की तख्तियां हाथों में थाम रखी थीं।

यह विरोध प्रदर्शन उस बढ़ते टकराव का संकेत है, जिसके तहत वैक्सीन विरोधी लंबे समय से यह कह रहे हैं कि अनिवार्य स्कूल वैक्सीन कानून सरकारी ज्यादती का प्रतीक है। कई लोगों को पहले से ही वैक्सीन साइंस पर संदेह है। कुछ का दावा है कि बचपन में लगे ये टीके ऑटिज़्म की वजह बनते हैं।

कानून बनने के बाद सुधरे

कैलिफोर्निया में हॉलीवुड हस्तियों और अमीरों के बीच दशकों से एंटी-वैक्सीन आंदोलन लोकप्रिय रहा है। 2015 में यहां बच्चों के लिए देश का सबसे सख्त अनिवार्य टीकाकरण कानून पारित किया गया था। इसके पहले पेरेंट्स बच्चों को टीका लगवाने से बचते थे। उनका तर्क होता था कि यह हमारी व्यक्तिगत मान्यताओं के खिलाफ है, लेकिन कानून के बाद टीकाकरण से बचने का विकल्प खत्म हो गया। कैलिफोर्निया में कोविड-19 के इस दौर में वैक्सीन विरोधियों ने खुद को ट्रम्प समर्थकों के ज्यादा नजदीक पाया है। राज्य में एंटी-वैक्सीन एक्टिविस्ट लंबे समय से आक्रामक रहे हैं, लेकिन पिछले दो वर्षों में और खास तौर पर कोरोनोवायरस महामारी के महीनों में उन्होंने टकराव और धमकी देने वाली रणनीति ज्यादा अपनाई है।

विधायक से मारपीट

विरोध में इन्होंने सैक्रामेंटो में एक विधायक के साथ मारपीट की और 2019 में स्टेट कैपिटल के सीनेट चैंबर्स में विधायकों पर खून तक फेंक दिया। पिछले महीने महिलाओं के एक समूह ने बजट की सुनवाई के दौरान सांसदों को धमकी दी थी कि हमने कुछ नहीं करने के लिए बंदूकें नहीं खरीदी हैं। इस मामले में स्टेट सीनेटर और बाल रोग विशेषज्ञ रिचर्ड पेन कहते हैं- चिंता की बात यह है कि विरोध करने वालों की संख्या बढ़ रही है। पेन ने ही टीकाकरण कानून तैयार किया था। वे कहते हैं कि यह आंदोलन न सिर्फ टीकाकारण के बारे में गलत जानकारियां प्रचारित कर रहा है, बल्कि ये उन लोगों को भी धमका रहे हैं जो इसके बारे में सही जानकारियां सामने ला रहे हैं।

बेसबॉल खिलाड़ी की मौत से घबराए

डोजर स्टेडियम पर प्रदर्शन करने गए लोगों का कहना है कि उन्होंने टीकारकरण स्थल में प्रवेश की कोशिश नहीं की। वे टीकाकरण के लिए गए लोगों को इसके बुरे प्रभावों के बारे में बताने गए थे। विरोध प्रदर्शन के प्रमुख जेसन लेफकोविट्ज ने कहा कि विरोध का कारण मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी हंक आरोन की मौत है। 86 वर्ष की उम्र में उनकी 22 जनवरी को मौत हुई। उन्हें 5 जनवरी को कोरोना का टीका लगा था।

यात्रियों की सुविधा के लिए कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर बढ़ाई गई एस्केलेटरों की संख्या

नई दिल्ली, (संवाददाता)। दिल्ली मेट्रो की ओर से यात्रियों की सुविधा में बढ़ोतरी की जा रही है। इसी दिशा में आज कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर 02 नए एस्केलेटरों सहित 09 मेट्रो स्टेशनों पर 10 अतिरिक्त एस्केलेटरों को चालू किया गया। इन दो नए एस्केलेटरों के लग जाने से अकेले कश्मीरी गेट स्टेशन पर ही एस्केलेटरों की रिकॉर्ड संख्या कुल 47 हो गई है। आपरेशन में आसान, नवीनतम सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट किए हुए इन नए एस्केलेटरों से यात्रियों को विशेषकर भीड़भाड़ वाली अवधि के दौरान सहूलियत मिल सकेगी। फिलहाल, दिल्ली मेट्रो के दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेटवर्क पर 389 कि.मी. के क्षेत्र में 285 स्टेशनों पर 1100 से अधिक एस्केलेटर स्थापित और चालू हैं। अन्य स्टेशन जहां यात्रियों की सेवा के लिए आज एक अतिरिक्त एस्केलेटर को चालू किया गया है उनमें रेड लाइन पर रिठाला और ब्लू लाइन पर उत्तम नगर (पूर्व), नवादा, राजौरी गार्डन, शादीपुर, यमुना बैंक, सुभाष नगर और आर. के. आश्रम मार्ग शामिल हैं। कश्मीरी गेट दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का एकमात्र ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन है जो लाइन-1 रेड लाइन लाइन-2 येलो लाइन और लाइन-6 वायलेट लाइन के बीच इंटरचेंज की सुविधा प्रदान करता है। यहां पर दो और एस्केलेटरों के जुड़ने के साथ, यह भारत का एकमात्र मेट्रो स्टेशन बन गया है, जहां विभिन्न स्तरों पर यात्रियों के आवागमन की सुविधा के लिए अनेक एस्केलेटरों की व्यवस्था है। इस स्टेशन पर मेट्रो नेटवर्क का सबसे लंबा एस्केलेटर है जिसकी ऊंचाई 14.5 मी. है, इससे बड़ा एस्केलेटर मैजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम पर स्थापित है, जिसकी ऊंचाई 15.6 मी. है।

अब सप्ताह में मिल सकती है 3 दिनों की छुट्टी

नई दिल्ली, (संवाददाता)। देश में बन रहे नए श्रम कानूनों के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में तीन दिन छुट्टी का प्रावधान संभव है। सोमवार को बजट में श्रम मंत्रालय के लिए हुए ऐलान पर जानकारी देते हुए श्रम सचिव ने बताया कि कि केंद्र सरकार हफ्ते में चार कामकाजी दिन और उसके साथ तीन दिन वैतनिक छुट्टी का विकल्प देने की तैयारी कर रही है। उनके मुताबिक नए लेबर कोड में नियमों में ये विकल्प भी रखा जाएगा, जिस पर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं। नए नियमों के तहत सरकार ने काम के घंटों को बढ़ाकर 12 तक करने को शामिल किया है। काम करने के घंटों की हफ्ते में अधिकतम सीमा 48 है, ऐसे में कामकाजी दिनों का दायरा पांच से घट सकता है। ईपीएफ पर टैक्स लगाने को लेकर बजट में हुए ऐलान पर और जानकारी देते हुए श्रम सचिव ने कहा कि इसमें ढाई लाख रुपये से ज्यादा निवेश होने के लिए टैक्स सिर्फ कर्मचारी के योगदान पर लगेगा। कंपनी की तरफ से होने वाला अंशदान इसके दायरे में नहीं आएगा या उस पर कोई बोझ नहीं पडेगा। साथ ही छूट के लिए ईपीएफ और पीपीएफ भी नही जोड़ा जा सकता। ज्यादा वेतन पाने वाले लोगों की तरफ से होने वाले बड़े निवेश और ब्याज पर खर्च बढ़ने की वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक 6 करोड़ में से सिर्फ एक लाख 23 हजार अंशधारक पर ही इन नए नियमों का असर होगा। वहीं न्यूनतम ईपीएफ पेंशन में बढोतरी के सवाल पर श्रम सचिव ने कहा कि इस बारे में कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा ही नहीं गया था। जो प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भेजे थे, उन्हें केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया है। श्रमिक संगठन लंबे समय से ईपीएफ की मासिक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पर सरकार न्यूनतम 2000 रुपये या इससे अधिक पेंशन मासिक रूप से दे रही है जबकि ईपीएफओ के अंशधारकों को अंश का भुगतान करने के बावजूद इससे बहुत कम पेंशन मिल रही है।

नई दिल्ली में सोमवार को दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

दिल्ली में गेस्ट हाउस संचालकों को बड़ी राहत, अब लाइसेंस के लिए नहीं होना होगा परेशान

नई दिल्ली । दक्षिणी दिल्ली के 12 मीटर तक के गेस्ट हाउस को अब बिना अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र (फायर एनओसी) के हेल्थ लाइसेंस मिल जाएगा। निगम ने इससे संबंधित नीति को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि रिहायशी क्षेत्र में जहां पर चौड़ी सड़क हो और यातायात बाधित न हो वहां पर भी लाइसेंस की मंजूरी दी जाएगी। निगम ऐसे गेस्ट हाउस में नया लाइसेंस भी देगा और पुराने गेस्ट हाउस के लाइसेंस को नवनीकरण भी करेगा। जिसकी फायर एनओसी की समय सीमा खत्म हो गई है उसको भी इस नीति के तहत लाभ मिलेगा।

दरअसल, इससे पूर्व निगम 12 मीटर तक के गेस्ट हाउस के लाइसेंस को उसी शर्त पर लाइसेंस देता था जब फायर से एनओसी मिल जाती थी। जबकि फायर विभाग यह कहते हुए ऐसे आवेदनों को रद्द कर देता था कि उसके नियमों में 12 मीटर तक के गेस्ट हाउस को एनओसी देने का

प्राविधान नहीं है। ऐसे में बहुत सारे लोग लाइसेंस से वंचित रह जाते थे। इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता था।

निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि गेस्ट हाउस संचालकों के लिए नीति का सरलीकरण किया गया है। इसमें 12 मीटर तक के गेस्ट हाउस को फायर से एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि गेस्ट हाउस संचालक को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना होगा। अधिकारी ने कहा कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसी आधार पर मिलता है जब कि अग्निशमन से बचाव के इंतजाम इमारत में कर रखे हो। इसलिए फिर फायर से एनओसी की जरुरत नहीं पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि राजधानी में दो हजार के करीब गेस्ट हाउस हैं। इसमें दक्षिणी निगम में 800 गेस्ट हाउस हैं।

12 मीटर से ज्यादा के लिए जरुरी है एनओसी

राजधानी में फिलहाल 12-15 मीटर तक ऊंचाई वाली ईमारतों में गेस्ट हाउस चलाने की अनुमति है। 12 मीटर तक फायर एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि इससे ज्यादा ऊंचाई वाली ईमारतों में गेस्ट हाउस चलाने के लिए एनओसी की आवश्यकता होगी।

25 ने लिया लाइसेंस

ओपन एयर रेस्तरां चलाने के लिए दक्षिणी निगम में नीति में लागू होने पर 25 रेस्तरां में ओपन एयर रेस्तरां के लिए लाइसेंस जारी कर दिए हैं। इससे निगम को करीब 50 लाख रुपये का राजस्व की आया है। निगम के अधिकारी ने बताया कि चूंकि फिलहाल फरवरी चल रहा है। नए वित्त वर्ष में आवेदनों की संख्या में बढोत्तरी होगी।

मैला ढोने वाले 48,687 लोगों में से केवल 30,246 लोगों को आर्थिक सहयोग का लाभ मिला

नई दिल्ली, (संवाददाता)। संसद की समिति ने इस बात पर निराशा व्यक्त की है कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पहचाने गए हाथों से मैला ढोने वाले 48,687 लोगों में से केवल 30,246 लोगों के पुनर्वास के लिए स्व रोजगार योजना के तहत एक मुश्त आर्थिक सहयोग प्रदान की गई है। समिति ने हाथों से मैला ढोने वालों के लिये बेहतर रोजगार के अवसर सृजित करने के महत्व को रेखांकित किया है, ताकि वे लोग गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। लोकसभा में पेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में यह बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए बैंक खातों, पते आदि के कथित तौर पर अधूरे विवरण के कारण हाथों से मैला ढोने वाले शेष लोगों को एक मुश्त आर्थिक सहयोग प्रदान नहीं की जा सकी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मार्च 2020 में सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र जारी किया था। समिति के विचार में एक मुश्त आर्थिक सहयोग को सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार हाथों से मैला ढोने वाले सभी लोगों को प्रदान की जानी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार, समिति यह भी ध्यान देती है कि हाथों से मैला ढोने वाले 9563 लोगों या उनके आश्रितों के एक छोटे से वर्ग ने अब तक कौशल विकास प्रशिक्षण का विकल्प चुना है।

गिरफ्तारी के साथ ही ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में आया दीप सिद्धू

नई दिल्ली, (संवाददाता)। किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर उपद्रव करने के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद ही सोशल मीडिया ट्विटर पर दीप सिद्धू टॉप 5 में ट्रेंड करने लगा। कई लोगों ने दीप सिंघु पर मीम्स भी शेयर किए, किसी ने कहा कि दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार करके सभी को हिला डाला। इसके अलावा नरेंद्र मोदी फैन क्लब से भी एक ट्वीट किया गया इसमें लिखा गया थैंक्यू यू दिल्ली, दीप सिद्धू की लेटेस्ट तस्वीर। शमा मोहम्मद ने ट्वीट किया कि को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। लाल किले की हिंसा के पीछे कौन है, यह समझने के लिए एक निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और जिसने उसे सुरक्षा की कई परतों को तोड़ने में मदद की। वह सरकार में उच्च रैंकिंग वाले व्यक्तियों के सक्रिय समर्थन के बिना इसे हासिल नहीं कर सकता था। गिरफ्तारी के बाद इस तरह के हजारों ट्वीट मीडिया पर वायरल हो गए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को पंजाब के जिरकपुर से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस दीप सिद्धू की गिरफ्तारी को लेकर जल्द ही अहम खुलासे कर सकती है।

बताया जा रहा है कि पूछताछ में दीप सिद्धू लाल किला हिंसा मामले में कई अहम खुलासे कर सकता है। उसने एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि अगर उसने मुंह खोला तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। इस मामले में भी दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है कि आखिर वो कौन से नाम थे जिसके बारे में उसने खुलासा करने की बात कही थी। पिछले सप्ताह ही दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू का सुराग देने पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। इसी के साथ दिल्ली पुलिस की कई टीमें दिल्ली-एनसीआर के साथ हरियाणा और पंजाब में लगातार छापेमारी कर रही थीं। इससे पहले रविवार को दिल्ली हिंसा में एक और आरोपित सुखदेव सिंह को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया था, उस पर 50,000 रुपये का इनाम था। दिल्ली पुलिस ने कुल 8 आरोपितों की गिरफ्तारी पर इनाम का एलान किया था, जिसमें दीप सिद्धू समेत 4 आरोपित बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने बताया था कि फरार दीप सिद्धू का फेसबुक अकांउट उसकी एक महिला मित्र संभाल रही है, जो विदेश में रहती है। दीप वीडियो रिकॉर्ड कर उसे भेज देता है और महिला दोस्त उसे फेसबुक पर अपलोड कर देती है। माना जा रहा है कि पुलिस की नजरों से बचने के लिए दीप सिद्धू ऐसा कर रहा है। दीप सिद्धू पुलिस को भटकाने के लिए ऐसा कर रहा है।

भारत का सबसे बड़ा पतंग बाजार पर मंडरा रहा मौत का साया, जरा सी चूक से हो सकता है बड़ा हादसा

नई दिल्ली । पुरानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में लोग इन दिनों बिजली के फैले तार के कारण परेशान हैं। बिजली, लैंडलाइन और अन्य तार लोगों के घर और छतों से टकराकर जा रहे हैं। इसके कारण लोगों को हादसों का डर सता रहा है। लोगों का कहना है कि वे इसकी शिकायत बिजली विभाग के अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अब तक तार नहीं हटाए जा रहे हैं। वहीं, पुरानी दिल्ली के बाजारों में भी तार के जाल फैलने से हादसों का खतरा बना हुआ, जिससे व्यापारियों को जान और माल का खतरा है।

दरियागंज के रहने वाले सलीम अहमद ने बताया कि पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार और सरकारी विभागों को इन्हें हटाने का आदेश दिया था, जिसकी रिपोर्ट विभागों को कोर्ट में देनी थी, लेकिन इसके बाद भी गलियों में तार के जाल फैले हुए हैं। उनका कहना है कि अकसर तारों में शार्ट सर्किट होता रहता है, जिसकी वजह से हादसा होने का डर लगा रहा है।

कई बार शार्ट सर्किट के कारण हादसे हो चुके हैं। लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। वहीं, लाल कुआं निवासी मोहम्मद नफीस ने बताया कि इलाके में भारत का सबसे बड़ा पतंग बाजार है, जिसमें आग लगने का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि शार्ट सर्किट के कारण पहले भी आग लगने जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। इसकी कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से भी शिकायत की है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।

वहीं, चांदनी चौक और भगीरथ पैलेस में भी तार के जाल फैले हैं, जहां व्यापारियों को भी हादसे का डर लगा रहता है। चांदनी चौक पर लटकते तार के जाल हटाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट नगर निगम, एमटीएनएल, बीएसईएस, मोबाइल टावर कंपनियों समेत अन्य एजेंसियों का निर्देश दे चुका है।

दिल्ली में अवैध कालोनियों को नियमित करने वाला बिल राज्यसभा से पास, लाखों लोगों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली । दिल्ली में अवैध कालोनियों को नियमित करने वाला बिल संसद के उच्च सदन राज्यसभा से पास हो गया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कानूनों (विशेष प्रविधानों) के दूसरे (संशोधन) विधेयक-2021 को सदन के पटल पर सोमवार को रखा था। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कानूनों (विशेष प्रविधानों) के दूसरे (संशोधन) अधिनियम, 2020 के स्थान पर सोमवार को यह विधेयक पेश किया था।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 दिसंबर, 2020 को इस अधिनियम को लागू करने की घोषणा की थी। इसके जरिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कानूनों (विशेष प्रविधानों) दूसरे अधिनियम, 2011 में संशोधन किया गया था। 2011 का यह अधिनियम 31 दिसंबर, 2020 तक ही वैध था। इस अधिनियम से इसकी समयसीमा बढ़कर 31 दिसंबर, 2023 तक हो गई है। 2011 के इस अधिनियम के जरिये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 31 मार्च, 2002 तक की अवैध कालोनियों का नियमितीकरण होगा। साथ ही एक जून, 2014 तक जहां कहीं भी निर्माण हुआ है, उसका भी नियमितीकरण होगा।

अब इस अधिनियम में संशोधन अवैध कालोनियों के नियमितीकरण की पहचान करने के लिए किया जा रहा है ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अवैध कालोनियों के निवासियों के संपत्ति अधिकारों की पहचान) अधिनियम, 2019 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अवैध कालोनियों के निवासियों के संपत्ति अधिकारों की पहचान) नियमितीकरण, 2019 के जरिये इन संपत्तिधारकों की सही पहचान हो सके। इसलिए एक जून, 2014 तक मौजूद रही अवैध कालोनियों और एक जनवरी, 2015 तक 50 फीसद विकास करने वाली कालोनियां नियमितीकरण के लिए उपयुक्त मानी जाएंगी। सरकार अब इस अधिनियम को इस बिल के जरिये कानून बनाना चाहती है।

दिल्ली-एनसीआर के लोगों को फिर से रुलाने लगा प्याज

नई दिल्ली, (संवाददाता)। दिल्ली-एनसीआर के लोगों को प्याज फिर से रुलाने लगा है। पिछले दो सप्ताह से लगातार प्याज के थोक और खुदरा दामों में बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को आजादपुर मंडी में प्याज 25 से 35 रुपये प्रति किलो में बेचा गया है। जो पिछले सप्ताह तक 20 से 25 रुपये प्रतिकिलो था। मंडी में प्याज की आवक भी प्रभावित हो गई है। प्याज के आढ़तियों का कहना है कि थोक भाव में बढ़ोतरी आवक में कमी के कारण हो रही है। प्याज के थोक भाव बढ़ने से खुदरा बाजारों में भी दाम बढ़ गए हैं। बाहरी दिल्ली इलाके की विभिन्न बाजारों में प्याज खुदरा में औसतन 40 से 70 रुपये प्रति किलो में बेचा जा रहा है। आजादपुर मंडी के अध्यक्ष आदिल अहमद खान का कहना है कि बारिश के चलते मंडी में भी प्याज के दाम बढ़े थे। लगातार इसके दामों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। गुरुवार को प्याज थोक भाव 30 से 50 रुपये किलो पहुंच गया था। आढ़तियों की मानें तो आने वाले कुछ दिनों तक प्याज का भाव और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं, दिल्ली के कई इलाकों में खुदरा बाजार में प्याज 70 से 80 रुपये किलो तक पहुंच गया है। इन दिनों आलू पांच से दस रुपये प्रतिकिलो में बिक रहा है। खुदरा बाजारों में भी आलू 10 से 15 रुपये में बेचा जा रहा है।

कोर्ट ने माना- पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही दंगाइयों ने किया नृशंस अपराध

नई दिल्ली। दिल्ली दंगा 2020 के दौरान पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सोमवार को कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की अदालत ने आरोपित आशीष कुमार को जमानत देने से इनकार दिया। अदालत ने आदेश में कहा कि दूसरे समुदाय का होने के कारण एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख कर बता रही हैं कि दंगाई भीड़ ने नृशंस अपराध को अंजाम दिया। गत वर्ष दंगे के दौरान करावल नगर इलाके में अपहरण कर सुलेमान नामक व्यक्ति कह हत्या कर दी गई थी। बाद में शव को प्रेम विहार पुलिया के पास नाले में फेंक दिया गया था।

इस मामले में आरोपित आशीष कुमार की जमानत अर्जी पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की अदालत में सुनवाई हुई।

बचाव पक्ष ने दलील दी कि आशीष कुमार को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। उसके खिलाफ झूठे गवाह खड़े किए गए हैं। वहीं, विशेष लोक अभियोजक ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए पक्ष रखा कि जिस दंगाई भीड़ ने डंडों से सुलेमान पर हमला किया, आरोपित आशीष कुमार उस भीड़ के पीछे खड़ा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में स्पष्ट नजर आ रहा है।

यह भी बताया कि कई चश्मदीद गवाहों ने आरोपित को दंगाई भीड़ में देखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई गवाह उसी क्षेत्र में रहते हैं, जहां आरोपित का घर है। ऐसे में वह गवाहों को डरा सकता है।

नहीं मिली अग्रिम जमानत

दंगे के दौरान शास्त्री पार्क इलाके में दंगे के दौरान उपद्रव, चोरी और डकैती के मामले में इस कोर्ट ने आरोपित रोहित नागर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

कोर्ट ने कहा कि दंगे की साजिश को उजागर करने के लिए न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है।

दिल्ली में कलस्टर बस में बम की सूचना से हड़कंप, बस से कूदकर भागे यात्री

नई दिल्ली । देश की राजधानी दिल्ली के आइटीओ इलाके मंगलवार दोपहर में उस समय अफरातफरी मच गई, जब वहां पर बस में बम की सूचना मिली। हालांकि, जांच में बैग में मेडिकल किट मिली। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों और दिल्ली पुलिस ने राहत की सांस ली। जागरण संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार दोपहर में आइटीओ के पास एक कलस्टर बस में बम मिलने की सूचना के बाद अफरातफरी मच गई। बस में बैठी सवारियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की।

वहीं, इस दौरान बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय दिया और बस को सड़क किनारे लगाया। इस दौरान ड्राइवर के चालक ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लगा। इसके बाद बस में सवार यात्रियों के फोन से दिल्ली पुलिस को कॉल किया गया और बस में रखे एक लावारिस सूटकेस की जानकारी दी गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम विस्फोटक की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने जांच की। वहीं, पुलिस ने जांच में पाया कि बैग में मेडिकल किट रखी हैं।

इसके बाद आसपास खड़े लोगों ने राहत की सांस लीं।इससे पहले 29 जनवरी को तुगलक रोड थाने से कुछ दूरी पर इजराइल दूतावास के बम धमाके हुए थे, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे टूटे थे। फिलहाल इस मामले की जांच एनआइए कर रही है। बम धमाका करने वाले तथाकथित आरोपितों ने एक लेटर बम भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह तो ट्रायल है।

भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली में संसद घेराव के विरोध के दौरान नारे लगाते हुए।

संपादकीय

शांत होते गुस्से का फिर भड़कना

सुलझती हुई गांठ एक नासमझी से किस कदर उलझ जाती है, गुरुवार देर शाम की घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है। गणतंत्र दिवस के दिन लोकतंत्र को अपमानित करने का दाग लगने के बाद किसानों ने दिल्ली की सीमा पर लगाए गए तंबुओं को हटाना शुरू कर दिया था। ऐसा लगने लगा था कि मामला संजीदगी से निपट रहा है और प्रशासनिक अधिकारी रास्ता खुलवाने में अब सफल हो जाएंगे। मगर सत्तारूढ़ दल के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं ने अति उत्साह में गलती कर दी और उन्हें जबर्दस्ती हटाने की कोशिश की। नतीजतन, जो तंबू स्वत- उखड़ रहे थे, वे फिर से जम गए। हमें यह समझना होगा कि किसान बहुत ही भावुक बिरादरी है। बेशक कृषक समुदायों में तमाम तरह के आपसी विरोध हों, लेकिन जब किसान देखते हैं कि कोई उनके हित के लिए लड़ रहा है और वह इतना अकेला हो गया है कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तब हर कोई एक हो जाता है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी यही हुआ। किसान नेता राकेश टिकैत के आंसू ने आंदोलनकारियों को फिर से एकजुट कर दिया, और खाली होती सड़कें दोबारा प्रदर्शनकारियों से भर गईं। सवाल अब भी वही है कि आखिर इस आंदोलन का अंत क्या है? चूंकि मध्यमार्ग सबसे मुफीद होता है, इसलिए बातचीत ही इस मसले का एकमात्र हल है। अब तक सरकार के प्रतिनिधि और किसान नेता 11 बार वार्ता की मेज पर आमने-सामने आ चुके हैं। सरकार इस पर सहमत हो गई है कि वह अगले डेढ़ साल तक नए कृषि कानूनों को लागू नहीं करेगी और कमेटी इन पर विचार करेगी, जिसमें किसानों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को भी पर्याप्त जगह दी जाएगी। हर आंदोलन का उद्देश्य दबाव बनाना होता है। और सरकार इतने दबाव में तो आ ही गई है कि उसने फिलहाल इन कानूनों से दूरी बरतना उचित समझा है। मौजूदा परिस्थिति में यही सबसे अच्छा समाधान है कि किसान नेताओं को इस पर तैयार हो जाना चाहिए।

हां, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) एक मुद्दा जरूर है। सरकार ने अभी इसे जारी रखने की बात कही है। मगर इसकी गारंटी से खरीदार व उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा, इसका भी अध्ययन जरूर होना चाहिए। इससे जन-वितरण व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन आवश्यक है। एमएसपी में संशोधन हो या नया कानून बने, इन सबकी एक तयशुदा प्रक्रिया होती है। उचित रास्ते से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस आंदोलन के आर्थिक असर से सरकार भी हलकान होगी। माना जा रहा है कि दिल्ली की सीमाबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को हर दिन 3,500 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। इस नुकसान की वजहें हैं, माल की ढुलाई में देरी, कर की वसूली न होना, जीएसटी इकट्ठा न होना, औद्योगिक क्षेत्रों की गतिविधियों का लगभग थम जाना आदि। देखा जाए, तो सरकार पर दोतरफा दबाव है। उसे आंदोलित किसानों को भी मनाना है और अपनी आर्थिक सेहत भी सुधारनी है। दबाव किसान नेताओं पर भी होगा। लाल किले की घटना से इस आंदोलन पर एक कलंक तो लग ही गया है। किसान नेता भी यह सोचने को मजबूर हुए होंगे कि भीड़ उतनी ही इकट्ठा की जाए कि वह अनुशासित रहे। उन्होंने आत्ममंथन जरूर किया होगा कि चूक कहां हो गई? अब वे भी अपना चेहरा बचाने की कोशिशों में हैं। पिछले दो दिनों से जिस तरह उत्तेजक बातें बंद हैं, यदि ऐसा पहले हुआ होता, तो 26 जनवरी की घटना शायद ही होती। हर आंदोलन की शुरुआत में ऊर्जा होती है, लेकिन वक्त बीतने के साथ-साथ उसमें हताशा का भाव आ जाता है और ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है। आवेश में ही सही, प्रदर्शनकारियों ने गलती तो कर ही दी। लिहाजा, अब इस आंदोलन का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। उचित समाधान तो यही है कि वार्ता जहां ठहर गई है, उसको आगे बढ़ाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी विशेषज्ञ समिति बनाई है। किसान नेताओं को इसके सामने भी पेश होना चाहिए। इन कानूनों को लागू न करने की एक समय-सीमा देकर आंदोलन का सम्मानजनक अंत किया जा सकता है। उन्हें आंदोलन को परिणाम की तरफ ले जाना चाहिए, न कि अकाल मौत की तरफ। इसमें गैर-राजनीतिक विचारों की भी सख्त जरूरत होगी। चर्चा किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में भी होनी चाहिए। यह जरूरी है कि यह बिरादरी न सिर्फ खुशहाल बने, बल्कि सामाजिक ताना-बाना भी मजबूत बना रहे। शुक्रवार को सिंघु बॉर्डर पर ग्रामीणों और किसानों में हुई झड़प इसी दरकते सामाजिक ताने-बाने का नतीजा है। दरअसल, दिक्कत यह है कि किसानों को वोट बैंक समझ लिया गया है। बेशक वे एकमुश्त किसी दल को मत नहीं देते, लेकिन उनके नाम पर जमकर राजनीति की जाती है। यह समझना होगा कि हर तबके के किसानों की समस्या अलग-अलग होती है। पंजाब के किसान मंडी और एमएसपी को लेकर मुखर रहते हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गन्ना बकाये को लेकर। मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए चावल मुद्दा होगा, तो केरल या दक्षिणी राज्यों के लिए नारियल। महाराष्ट्र में प्याज, बुंदेलखंड और गुजरात में दाल उत्पादन से जुड़े किसान परेशान हो सकते हैं। फसल का यदि सही मूल्य नहीं मिलता, तो बर्बादी आती ही है। राजनेता इसी आग में अपनी रोटी सेंकना चाहते हैं। कोई इन मसलों का ठोस समाधान नहीं चाहता, बल्कि मुद्दों को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, ताकि किसानों के वोट उन्हें मिलते रहें। राजनेताओं को इन मुद्दों को हवा नहीं देना चाहिए। नहीं भूलना चाहिए कि कोविड-19 महामारी में भी यह खेतिहर समाज ही है, जिसके कारण हमें तुलनात्मक रूप से कम नुकसान हुआ है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि किसानों की उर्वरता बची रहे। इस तरह की अफरातफरी के कई नुकसान हैं। दुश्मन देश भी इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे, लाल किले पर एक धर्मविशेष के प्रतीक चिह्न का झंडा लहराया गया, तो उसे पाकिस्तान के ट्विटर हैंडलर ने खालिस्तानी झंडे के रूप में प्रचारित किया। साफ है, ऐसे लंबे आंदोलन न सरकार के हित में हैं, न देश के और न ही आंदोलनकारियों के, पर बड़ा नुकसान आम आदमी को होता है, क्योंकि इन आंदोलनों से होने वाले आर्थिक नुकसानों की भरपाई की जेब से की जाती है।

प्रवीण कुमार सिंह

पाकिस्तानी सेना के उत्पीड़न से त्रस्त होकर जोर पकड़ती अलग सिंधु देश की मांग

जबकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की आर्मी पंजाबियों के अलावा किसी और संस्कृति के लोगों को सत्ता के लिए दूर की कौड़ी समझती है। विडंबना देखिए कि बलूच रेजिमेंट में एक भी बलूची जवान की भर्ती नहीं होती। वर्तमान पाकिस्तान के करीब 70 प्रतिशत क्षेत्र में सिंध और बलूचिस्तान है, जबकि यहां उच्च शिक्षा का ढांचा सबसे कमजोर है। ऐसे और भी बहुत से कारण हैं, जिससे वहां की जनता आज आंदोलित है और अपनी मांगों के समर्थन में सड़क पर है। ऐसे में भारत को इस मामले में कूटनीति के स्तर पर आगे बढ़ना चाहिए।

पाकिस्तानी लेखक और विचारक हसन निसार का कहना है, समय के साथ अगर आवश्यकताएं बदलती हैं तो हमें नियम भी बदलने चाहिए, नहीं तो शासन करने की राजनीति स्थिर और जड़ हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में ही शासन के तौर-तरीकों में इतना जबरदस्त भेदभाव है कि बलूच, पख्तून, गिलगिट बाल्टिस्तान, के बाद सिंध प्रांत में आजाद सिंधु देश की मांग जोर पकड़ती जा रही है।

वर्तमान पाकिस्तान में प्राप्त राजस्व का करीब 80 प्रतिशत कर सिंध प्रांत से आता है और इस कर के माध्यम से जो रुपया पाक आर्मी के पास पहुंचता है, उसकी संगठित लूट पंजाबी मुसलमान ब्यूरोक्रेसी करती है। जबकि खर्चे में सिंध प्रांत की हिस्सेदारी मात्र 22 प्रतिशत दिया जाता है। पाक की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था वहां की आर्मी के जूते साफ करने के सिवाय कुछ नहीं कर पाती, सारे बड़े निर्णय पंजाबी आर्मी व ब्यूरोक्रेसी करती है। पाकिस्तान मामलों के जानकार और पूर्व पाकिस्तानी नागरिक व अब यूरोप में निर्वासित जीवन जी रहे आरिफ अजाकिया के अनुसार पाकिस्तान की आर्मी नागरिक कानूनों को जूते की नोक पर रखती है।

सिंधियों की अपनी एक अलग और स्वतंत्र सभ्यता थी, जिसे पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी रौंद देने पर आमादा है। अजाकिया कहते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी एक आर्टिफिशियल देश है, यहां पर जिहादी मानसिकता के मौलाना और पंजाबी मुस्लिम आर्मी व ब्यूरोक्रेसी के साथ अन्य समुदायों का रहना नामुमकिन है। सिंध के राष्ट्रवादी नेता जीएम सईद को बांग्लादेश बनने के पश्चात ही यह समझ में आ गया था कि सिंध के लोगों का पाकिस्तानी फौजी हुकूमत के साथ रहना मुश्किल है। जीएम सईद वही शख्स थे जो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक स्वतंत्र मुस्लिम पाकिस्तानी देश बनाने के बहुत पक्के हिमायती और पक्षकार थे। जीएम सईद का कहना था कि सिंधु सभ्यता और सिंध नदी मानव सभ्यता का संदेश देने वाली पहली सभ्यता थी।

हालांकि पाकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होने के पश्चात जिस प्रकार बलूच अपनी आजादी की मांग को लेकर लगातार सक्रिय रहे, उसी प्रकार सिंधु देश की मांग को लेकर जीएम सईद ने माना कि पाकिस्तान की अहंकारी पंजाबी फोर्स कभी सिंधियों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकती। अत- सिंधी भाषा, सिंधी सभ्यता और सिंधी लोगों के लिए स्वतंत्र सिंध देश का निर्माण होना चाहिए, चाहे वह सिंधी हिंदू हो या मुसलमान, वह एक गुलदान की तरह है। सिंध प्रांत में प्रदर्शनकारियों की मांग है कि चीन को आखिर सिंध की जमीन क्यों दी जा रही है? चीन अपने यहां सामरिक हितों को साधने में लगा हुआ है और सिंधियों के अधिकारों का हनन कर रहा है। साथ ही, वह उनके संसाधनों पर डाका डाल रहा है। सिंध के प्राकृतिक संसाधनों को अपने कब्जे में ले रहा है।

आखिर सिंधियों की आजादी की मांग को वाजिब क्यों न माना जाए। जिस पाक चीन की दोस्ती पर इमरान की सरकार इतरा रही है, क्या उसे समझ नहीं आता है कि उसका मुस्लिम दोस्त मलेशिया कर्ज न चुकाने के कारण उसका विमान अपनी धरती पर रोक लेता है और कहता है पहले इमरान खान कर्जा चुकाएंगे, उसके बाद विमान को जाने देंगे। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली स्थिति पाकिस्तान के लिए और क्या हो सकती है? जो देश कर्ज के कारण अपने विमान गिरवी रखने पर मजबूर हो जाता है, क्या वह चीन के कर्ज के तले दबे होने के बाद अपनी जमीन चीन से दोबारा हासिल कर पाएगा?

उल्लेखनीय है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अभी सबसे ज्यादा हिंदू और ईसाई सिंध प्रांत में रहते हैं। लिहाजा इस पूरे मामले पर भारत को पैनी नजर रखने की जरूरत है। गिलगिट बाल्टिस्तान जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा है, चीन पाक आर्थिक गलियारा के नाम पर यहां से लेकर सिंध और बलूचिस्तान होते हुए ग्वादर पोर्ट तक नई सड़क बना रहा है।

पाकिस्तान की धरती पर तालिबानियों को खड़ा करने में पाकिस्तान आर्मी की ही सबसे बड़ी भूमिका थी और उसमें सबसे ज्यादा पख्तून ही भर्ती करवाए गए थे। अब पाकिस्तान आर्मी ने तालिबान को दिखावटी तौर पर समाप्त करने के नाम पर पख्तून नौजवानों के खिलाफ लगभग युद्ध छेड़ दिया है। बलूची और सिंधियों की तरह ही पख्तून बहुत ही बहादुर कौम है। बलूची नौजवानों की तरह ही पख्तून राष्ट्रवादियों ने तो नारा भी दे दिया है- यह जो दहशतगर्दी है, उसके पीछे वर्दी है।

फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब एरिया, (फाटा) खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौज के भय की सीमा पार हो चुकी है और अब विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी है। अगर पख्तूनों और बलूचों का सहयोग सिंध राष्ट्रवादियों को मिला तो पाकिस्तान का संघीय ढांचा स्वत- खतरे में आ जाएगा। पाकिस्तान मामलों के बुद्धिजीवियों का कहना है कि पूरे पाकिस्तान में वर्दी का जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप एक और 1971 रक्त रंजित गृह युद्ध को बहुत जल्द पाकिस्तान में दोहरा सकता है।

पाकिस्तान के लेखक और कनाडाई नागरिक तारिक फतेह के अनुसार, राज्य चलाने में समस्त देश की विभिन्न संस्कृतियों की पहचान कर सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। जबकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की आर्मी पंजाबियों के अलावा किसी और संस्कृति के लोगों को सत्ता के लिए दूर की कौड़ी समझती है। विडंबना देखिए कि बलूच रेजिमेंट में एक भी बलूची जवान की भर्ती नहीं होती। वर्तमान पाकिस्तान के करीब 70 प्रतिशत क्षेत्र में सिंध और बलूचिस्तान है, जबकि यहां उच्च शिक्षा का ढांचा सबसे कमजोर है। ऐसे और भी बहुत से कारण हैं, जिससे वहां की जनता आज आंदोलित है और अपनी मांगों के समर्थन में सड़क पर है। ऐसे में भारत को इस मामले में कूटनीति के स्तर पर आगे बढ़ना चाहिए।

आवश्यकता है प्रशासनिक सुधारों की जिससे सरकार की कार्य क्षमता में वृद्धि हो

पिछले कुछ दशकों में अर्थव्यवस्था और समाज में भारतीय राज्य की भूमिका के बारे में सार्वजनिक विमर्श एक गलत परिपाटी पर चला गया है। नेहरूवादी राज्य और समाजवादी नीतियों की विफलता ने सरकार और विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया को उत्पन्न किया। लाइसेंस-कोटा परमिट राज, अक्षम नौकरशाही और बेलगाम भ्रष्टाचार ने सरकारी व्यवस्था के विरुद्ध माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके चलते सरकार को समस्या के समाधान नहीं, बल्कि समस्या के जनक के रूप में देखा जाने लगा। इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि 1990 के दशक के बाद से सरकार के आकार को कम करने का तर्क व्यापक समर्थन पाने लगा। खासतौर पर शहरी मध्य वर्ग और नीति निर्माताओं द्वारा सरकार में सुधार करने की वकालत की जाने लगी। महत्वपूर्ण मुद्दा यह बना कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या को कम करना है। इसके पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि सरकारी क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा नौकरियां हैं, जिन्हें कम करके सरकारी घाटे को कम किया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का रोजगार -अनुपात दुनिया में सबसे कम है।

सातवें वेतन आयोग के अनुसार अगर रेलवे और डाक विभाग को निकल दिया जाए तो प्रत्येक 1,00,000 लोगों के लिए केवल 139 सरकारी कर्मचारी हैं। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बाजारवादी और कथित तौर पर न्यूनतम सरकार वाले देश में प्रति 1,00,000 निवासियों पर 668 सरकारी कर्मचारी हैं। भारत में ज्यादातर सरकारी कर्मचारी रेलवे, डाक विभाग, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के तहत काम करते हैं, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या न के बराबर है।

वर्ष 2014 में अकेले केंद्र सरकार के स्तर पर 7,50,000 रिक्तियां थीं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लगभग 38 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। राज्यों की नौकरशाही में वर्षों से मध्यम स्तर के पदों पर भर्ती नहीं होने के कारण पूरा सरकारी तंत्र ही विलुप्त होता जा रहा है। इसे देखते हुए सरकारी नौकरियों में कटौती करने के बजाय भारत को राज्य की क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। यह समझा जाना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार का अभिप्राय कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना नहीं है। आवश्यकता तो उसका पुनर्गठन करने की है। समस्या यह है कि सरकार को जिस क्षेत्र में होना चाहिए, वहां नहीं है और बेवजह के ऐसे सरकारी विभागों का बोलबाला है, जिनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुश्किल यह है कि समाजवादी समय की बनाई हुई व्यवस्था आज तक चली आ रही है। जिस तरह पुलिस के तमाम पद रिक्त हैं, उसी तरह स्कूलों में बड़े पैमाने पर रिक्तियां हैं। यदि सभी राज्यों को मिला दिया जाए तो अकेले स्कूलों में करीब दस लाख पद खाली पड़े हुए हैं। ग्रामीण और कृषि मंत्रालय में लगभग 30 प्रतिशत रिक्तियां हैं, जिनमें अधिकांश का कार्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने का है। यहां तक कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लंबे समय से नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। कुछ मामलों में 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां हैं। राज्य स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थिति इतनी दयनीय है कि बात न करना ही बेहतर है। अगर देश में पुलिस, स्कूल, अस्पतालों में लाखों रिक्तियां हैं तो इसका मतलब है कि भारतीय राज्य का अस्तित्व सिर्फ कागजों में है। आखिर ऐसे में सरकार का आकार कम करने की बात ही कहां आती है? जब सरकार सिर्फ नाममात्र के लिए हो तो उसका आकार कम करना न्यायसंगत कैसे हो सकता है? किसी के लिए भी यह बुनियादी बात समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि अगर अधिक न्यायाधीश होंगे तो हमारी न्यायिक प्रणाली तेजी से न्याय देना सुनिश्चित करेगी। इसी तरह अधिक पुलिसकर्मियों का मतलब बेहतर कानून एवं व्यवस्था से होगा। इसी क्रम में और अधिक डॉक्टरों का मतलब होगा आम आदमी के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल। स्कूलों और कॉलेजों में सही पढ़ाई होने से देश का मानव संसाधन कहीं अधिक सक्षम और बेहतर होगा। ये सभी पद आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। केवल कल्पना की दुनिया में ही ये पद आर्थिक विकास पर बोझ माने जा सकते हैं।

सरकारी तंत्र में सुधार का यह मतलब नहीं और न हो सकता है कि सरकारी तंत्र को ही समाप्त कर दिया जाए। सरकारी कर्मचारियों को उचित मानदंड देने में असमर्थता या अनिच्छा का मतलब यह नहीं है कि सरकार लोगों को काम पर रखना ही बंद कर दे। दरअसल समस्या कभी भी सरकारी कर्मचारियों की संख्या की नहीं रही है। वह तो हमेशा ही बेहद कम रही है। बतौर उदाहरण मात्र पचास लाख की आबादी वाले छोटे से सिंगापुर की विदेश सेवा में भारत के विदेश सेवा विभाग से ज्यादा अधिकारी हैं। असली समस्या नौकरशाही के हाथों में अत्यधिक और मनमानी शक्तियों की है।

महामारी कोविड-19 के दौरान हमने नौकरशाही राज को देखा कि उसने किस तरह चार महीने के अंदर लॉकडाउन संबंधी सैकड़ों नियम जारी कर एक तरह से अराजकता की स्थिति पैदा कर दी थी। भारत में सरकार का आकार ज्यादा बड़ा इसलिए लगता है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के पास अनाप-शनाप शक्तियां हैं।

सरकारी बॉन्ड में रिटेल इन्वेस्टर

रिजर्व बैंक ने बीते शुक्रवार छोटे निवेशकों को डायरेक्ट ऑनलाइन ऐक्सेस के जरिए सरकारी बॉन्ड खरीदने की इजाजत देने की बड़ी घोषणा की। उम्मीद है कि यह कदम न केवल सरकार के संसाधनों में इजाफा करके इकॉनमी को गति देने की उसकी कोशिशों को मजबूती देगा बल्कि छोटे निवेशकों को सुरक्षित निवेश का एक अच्छा विकल्प भी मुहैया कराएगा। संसद में पेश आर्थिक सर्वे और फिर 2021-22 के बजट से साफ है कि सरकार की योजना इन्फ्रास्ट्रक्चर के मद में निवेश अधिकाधिक बढ़ाकर इकॉनमी को मंदी के दौर से निकालने और विकास की रफ्तार तेज करने की है। जाहिर है, इसके लिए उसे अपने वित्तीय संसाधन बढ़ाने के नए इंतजाम करने पड़ेंगे। 2020-21 और 21-22 के बढ़े हुए वित्तीय घाटे के अनुमान को ध्यान में रखें तो सरकार को इन दोनों वर्षों में क्रमश: 12.8 लाख करोड़ और 12 लाख करोड़ रुपये उधार लेने होंगे। रिजर्व बैंक का ताजा फैसला इस मामले में सरकार की मुश्किल आसान कर सकता है। इससे इन्वेस्टर बेस बड़ा होगा और सरकार को बड़ी परियोजनाओं के लिए धन जुटाने का एक और जरिया मिल जाएगा।

जहां तक निवेशकों का सवाल है, सुरक्षित निवेश के पारंपरिक ठिकाने जैसे जमीन, फ्लैट और सोना वगैरह अब सुरक्षित नहीं माने जा रहे हैं क्योंकि पैसा कहीं भी फंस सकता है। रियलिटी सेक्टर की बदहाली जगजाहिर है और सोने के भाव ने जिस तेजी से 50 हजार रुपये प्रति दस ग्राम की रेखा पार की है, उसे देखते हुए निवेशक की यह आशंका स्वाभाविक है कि इतने महंगे रेट के सोने या गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाने से कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। रिटेल इन्वेस्टर्स की सरकारी बॉन्ड्स तक सीधी पहुंच बनाने की यह पहल सुरक्षित निवेश का ठिकाना ढूंढ रहे छोटे निवेशकों के लिए मुंहमांगी मुराद पूरी होने जैसी है। लेकिन ढांचागत सुधार के इस महत्वपूर्ण फैसले के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। अव्वल तो यही देखना होगा कि इससे निवेशकों का उत्साह वास्तव में बढ़ता भी है या नहीं। छोटे निवेशकों के पास अप्रत्यक्ष ढंग से ही सही पर बॉन्ड में निवेश करने का डेट फंड वाला विकल्प तो अब भी है ही। उसकी राह अब पहले के मुकाबले आसान जरूर हो रही है। ऐसे में अगर निवेशक सचमुच इस विकल्प की तरफ खिंचते हैं तो एक सवाल यह रहेगा कि कहीं इसका असर बैंकों की जमा पर न पड़े। यानी रिटेल इन्वेस्टर इसे बैंक डिपॉजिट्स का विकल्प न बनाने लग जाएं। हालांकि आरबीआई ने इस डर को खारिज किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रिजर्व बैंक सुधार की उस राह पर कदम बढ़ा रहा है जिसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। अमेरिका के अलावा ब्राजील दुनिया का वह इकलौता देश है जहां यह कदम उठाया गया है। जाहिर है, हमें अपने देश की स्थितियों और यहां की जरूरतों के अनुरूप अपने अनुभव से सीखते हुए बढ़ना है। उम्मीद करें कि रिजर्व बैंक इस दिशा में हर नई पहल को लेकर पर्याप्त सावधानी बरतेगा।

भारतीय लोकतंत्र को बंधक बनाने वाला किसान आंदोलन ने राष्ट्र को शर्मसार कर उस पर एक धब्बा लगा दिया

आंदोलनों के माध्यम से लोकतांत्रिक सरकारों का ध्यान सामाजिक सरोकारों की ओर खींचना जरूरी है, पर इसके लिए आंदोलन का स्वरूप स्वतंत्र और स्वायत्त होना अपरिहार्य है। राजनीतिक दलों द्वारा हाईजैक होने से आंदोलनों की धार कुंद हो जाती है। सामाजिक आंदोलनों का लोकतंत्र में सदैव स्वागत है, लेकिन उन्हें भारतीय लोकतंत्र को बंधक बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसान आंदोलन ने लोकतंत्र को बंधक ही नहीं बनाया, उसे शर्मसार कर उस पर एक धब्बा भी लगा दिया।

दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर वही हुआ, जिसकी आशंका थी। कृषि कानूनों के विरुद्ध दो महीने से चल रहे किसान आंदोलन ने हिंसक और राष्ट्रविरोधी स्वरूप लेकर गण, तंत्र और गणतंत्र, तीनों को शर्मसार किया। जिस पंजाब ने तिरंगे की शान के लिए अपने असंख्य सपूतों का बलिदान दिया, उसी पंजाब से किसानों का मुखौटा लगाए धनपतियों के अराजक साथियों द्वारा लाल किले पर तिरंगे का अपमान पंजाब और देश के नाम पर धब्बा लगाने जैसा है। इस प्रकरण में गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के धैर्य की तारीफ करनी होगी, अन्यथा लाल किले में अनर्थ हो सकता था। वास्तव में सामाजिक आंदोलनों पर किसी भी संगठन या नेता का इतना नियंत्रण नहीं होता कि वह उसे अनुशासित रख सके और एक छोटे समूह द्वारा अचानक की गई अराजकता को रोक सके। जैसा अपेक्षित था, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने हिंसा की तमाम वारदातों और लाल किले की घटना से अपना पल्ला झाड़ लिया। कुछ ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली, लेकिन आखिर किसानों को कृषि कानूनों पर गुमराह करने, कानून वापस लेने के लिए उकसाने और गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद के बाद अब इसका क्या औचित्य?

कृषि कानूनों के विरोध पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक समिति भी बनाई, जिसे किसानों की बात सुनकर अपनी रिपोर्ट देनी है। सरकार ने भी किसान नेताओं से कई दौर की वार्ता कर किसी हल पर पहुंचने की कोशिश की। सरकार इसके लिए भी

तैयार थी कि डेढ़ वर्ष तक इन नए कानूनों को स्थगित रखा जाए, लेकिन किसान नेताओं ने अड़ियल रुख अपना कर भारतीय लोकतंत्र को बंधक सा बना लिया। हम विदेशी ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अपनों का क्या करें? ऐसा ही असफल प्रयोग नागरिकता कानून पर किया गया था, जो कई माह बाद दिल्ली में भीषण हिंसा के बाद खत्म हुआ। यह ध्यान रहे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन दोनों आंदोलनों का नेतृत्व किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने और मोदी विरोध के प्रयास में वे राष्ट्रविरोधी ताकतों के शिकंजे में फंसते जा रहे हों?

अपने देश में सामाजिक आंदोलनों की गौरवशाली परंपरा रही है। हाल में अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकपाल आंदोलन चलाया, जिसे अपार जनसमर्थन मिला। अन्ना आंदोलन का स्वरूप सुधारात्मक था। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनवाना चाहता था, जबकि किसान आंदोलन का स्वरूप प्रतिरोधात्मक है। यह कानूनों को समाप्त कराना चाहता है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में भीड़ जुटाना कठिन नहीं, लेकिन उसके द्वारा कानून वापस लेने का दबाव डालना एक गलत नजीर है। कल किसी और कानून को वापस लेने की ऐसी ही मांग उठ सकती है। नए कृषि कानून ढांचागत सुधारों की तरफ साहसी कदम हैं, लेकिन यदि इनसे किसानों को कोई राहत नहीं मिली तो भावी सरकारें इन्हें संशोधित या निरस्त कर सकती हैं। आखिर इन कानूनों से इतना डर क्यों? ऐसा ही भ्रम तब पैदा किया गया था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण लागू किया। तब शंका थी कि अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और विदेशी कंपनियां देसी उद्योगों का खात्मा कर देंगी। पिछले 30 वर्षों का अनुभव इसके विपरीत रहा। इस दौरान अर्थव्यवस्था में नौ गुना और बजट में 19 गुना वृद्धि हुई तथा विदेशी मुद्रा भंडार 5.8 अरब डॉलर से सौ गुना बढ़ कर 580 अरब डॉलर हो गया है।

किसानों के लिए महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन ने प्याज, गन्ना और कपास के दामों को लेकर अनेक आंदोलन किए। शेतकारी संगठन हमेशा किसानों के लिए खुले बाजार की मांग करता रहा है, लेकिन अनेक राज्यों के कानूनों ने किसानों को उत्पाद बेचने के लिए मंडियों और अढ़तियों का बंधक बना दिया है। नए कृषि कानून उन्हें बंधनमुक्त करना चाहते हैं, लेकिन जो छोटे किसान इससे लाभान्वित हो सकते हैं, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं। नए कृषि कानूनों को अगले तीस वर्षों के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। यदि किसानों की आय बढ़ाना है तो एमएसपी की गारंटी उसका समाधान नहीं। उसके लिए किसान को कृषि उत्पादक से कृषि व्यापारी बनाना पड़ेगा। अभी किसान केवल फसल पैदा करने में मशगूल रहता है। नए कृषि कानून ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि किसानों का ग्रामीण संगठन बने। वे सामूहिक रूप से एकजुट होकर पंचायत स्तर पर बड़े व्यापारियों से लाभकारी अनुबंध कर सकें और विक्रय एवं लाभकारी मूल्य की चिंता से मुक्त हो खेती कर सकें। इससे किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा मूल्य मिल सकेगा। इससे पंचायत स्तर पर भंडारण की सुविधाएं विकसित होंगी, जिससे किसान तब अपना उत्पाद बेच सके, जब उसे उचित मूल्य मिले। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर मार्केटिंग अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दिल्ली में जमा किसान नेता यह सब समझने को तैयार नहीं।

सामाजिक आंदोलनों से जनता की आस्थाएं इसीलिए खत्म हो रही हैं, क्योंकि वे प्राय- राजनीतिक तत्वों या दलों द्वारा हथिया लिए जाते हैं। अन्ना आंदोलन को अरविंद केजरीवाल ने, कम्युनिस्टों के आंदोलन को सीपीआइ एवं सीपीएम ने हथियाया। स्वतंत्रता आंदोलन को कांग्रेस ने और शेतकारी संगठन को शरद पवार ने। आज स्थिति यह है कि किसान आत्महत्या में महाराष्ट्र सबसे आगे है। अन्ना का लोकपाल लुप्त हो गया है। कम्युनिस्टों की पूर्ण क्रांति का पता नहीं और कांग्रेस पतन की ओर है। किसान आंदोलन अराजक तत्वों के हत्थे चढ़ गया। आंदोलनों के माध्यम से लोकतांत्रिक सरकारों का ध्यान सामाजिक सरोकारों की ओर खींचना जरूरी है, पर इसके लिए आंदोलन का स्वरूप स्वतंत्र और स्वायत्त होना अपरिहार्य है। राजनीतिक दलों द्वारा हाईजैक होने से आंदोलनों की धार कुंद हो जाती है। सामाजिक आंदोलनों का लोकतंत्र में सदैव स्वागत है, लेकिन उन्हें भारतीय लोकतंत्र को बंधक बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसान आंदोलन ने लोकतंत्र को बंधक ही नहीं बनाया, उसे शर्मसार कर उस पर एक धब्बा भी लगा दिया।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

यूपी में सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कांग्रेस चलाएगी किसान आंदोलन, शामिल होंगे वरिष्ठ नेता

लखनऊ । बेशक, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली सीमा पर चल रहे किसानों के आंदोलन को समर्थन का खाद-पानी विपक्षी दल ही शुरू से दे रहे हैं, लेकिन किसान नेता इस पर राजनीतिक छाप नहीं पड़ने देना चाहते। ऐसे में सरकार के खिलाफ माहौल बनाने और भुनाने का तानाबाना बुनना गैर-भाजपाई दलों ने शुरू कर दिया है। इसी प्रयास में कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में अपना किसान आंदोलन खड़ा करना चाह रही है। इसके लिए बुधवार से तहसील किसान पंचायतें शुरू की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस किसान आंदोलन की रूपरेखा कई माह पहले भी बना रही थी। पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश पदाधिकारी ने बताया कि दस से 21 फरवरी तक प्रदेश के 24 जिलों में तहसील किसान पंचायतें की जाएंगी। तहसील का कोई न कोई गांव पंचायत के लिए चुना जाएगा। इनमें प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सहित सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान और पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक व वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। हाईकमान ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन पंचायतों में सभी नेताओं को भागीदारी करनी है। इन कार्यक्रमों के जरिये पार्टी कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास करेगी। इन पंचायतों के अलावा कुछ विकासखंडों में भी पंचायतें की जाएंगीं।

एक पदाधिकारी के जिम्मे होगा एक जिला - किसान पंचायत के साथ ही पार्टी आगामी सभी आंदोलनों के लिए अपनी तैयारी मजबूत करने में जुटी है। बताया गया है कि प्रदेश की कमान संभालने पर राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने छोटी प्रदेश कार्यकारिणी का फार्मूला दिया था। फिर जरूरत के अनुसार पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाती रही। अब तय हुआ है कि संगठन में और विस्तार कर प्रदेश टीम का आकार कम से कम 75 पदाधिकारियों का किया जाएगा, ताकि किसी भी कार्यक्रम के लिए एक-एक पदाधिकारी को एक-एक जिले की जिम्मेदारी दी जा सके।

गढ़वा के इस पंचायत में मुर्दे भी उठा रहे राशन, 24 लाभुक एक ही परिवार से

गढ़वा । गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर प्रखंड में जन वितरण प्रणाली में व्याप्त गड़बड़झाला समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रखंड के अंतर्गत कोलझिकी पंचायत में जन वितरण प्रणाली में भारी गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है। यहां सुविधा संपन्न लोगों के साथ मुर्दे भी राशन का उठाव कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार पंचायत में 42 अंत्योदय के लाभुकों में से 24 लाभुक एक ही परिवार से संबंधित हैं। वैसे लाभुक भी अंत्योदय का लाभ उठा रहे हैं, जिनके पास पक्का मकान, चार पहिया वाहन और अछी खासी जमीन है। और तो और, वर्षों पहले मृत हुए व्यक्ति के नाम पर भी राशन का उठाव हो रहा है। सरकारी सेवा से रिटायर कर्मी भी राशन ले रहे हैं। यहां पीडीएस में भारी लूट मची हुई है। जानकारी के अनुसार कोलझिकी निवासी संतोष चन्द्रवंशी की मौत लगभग चार साल पहले हो चुकी है। लेकिन संतोष के नाम पर बड़े आराम से राशन का उठाव हो रहा है। संतोष का पीएच राशन कार्ड नंबर 202000089636 है। पीडीएस डीलर आरती महिला विकास समिति की दुकान से निरंतर राशन का उठाव हो रहा है।

सुदर्शन राम सरकारी शिक्षक के पद से रिटायर हुए हैं। साथ ही वर्तमान में पेंशनर हैं। उन्हें भी राशन का लाभ मिल रहा है। देवरानी देवी जो उनकी पत्नी हैं, उनके नाम से राशन कार्ड नंबर 202007173857 में उनके पति रिटायर शिक्षक सुदर्शन राम, पुत्र लाल कुमार और उनकी पारा शिक्षक बहु ममता वर्मा का नाम शामिल है। डीलर उर्मिला देवी के यहां से निरंतर राशन का उठाव हो रहा है। कोलझिकी निवासी गोपाल चन्द्रवंशी बीएलओ हैं और लोक शिक्षा केंद्र कोलझिकी के प्रभारी हैं। कोलझिकी गांव और श्री बंशीधर नगर शहर में पक्का मकान है। अछी खासी जमीन भी है। पत्नी रेखा देवी आंगनबाड़ी सेविका हैं। गोपाल चन्द्रवंशी की पत्नी रेखा देवी के नाम पर अंत्योदय कार्ड है। इसकी संख्या 2024089386 है। कार्ड से लक्ष्मी महिला विकास समिति के दुकान से निरंतर राशन का उठाव हो रहा है। लक्ष्मी महिला विकास समिति के संचालक गोपाल चन्द्रवंशी के परिवार के हैं। पीडीएस में गड़बड़ी के विषय में पंचायत की पूर्व मुखिया सविता देवी बताती हैं कि डीलर की मनमानी के कारण योग्य लाभुकों के बजाय साधन संपन्न लोग लाभ उठा रहे हैं। संतोष चन्द्रवंशी की मौत के बाद भी उनके नाम पर राशन का उठाव पूरी तरह अवैध है। इस संबंध में डीलर विनोद चंद्रवंशी ने कहा कि यह पूरे पीडीएस सिस्टम को कठघरे में खड़ा कर देने वाला है। बकौल विनोद चन्द्रवंशी इस तरह का मामला सिर्फ उनके पास ही नहीं है, अन्य डीलरों के यहां भी मृत्यु के बाद लाभ मिल रहा है।

नोकझोंक के बाद रस्सी से गला कसकर पत्नी को मार डाला, कमरे में शव को छोड़कर भाग निकला पति

मानपुर (गया)। गया जिला के मानपुर स्थित पटवा टोली के बैदनाथ सहाय लेन के समीप सोमवार की रात ट्रक चालक ने रस्सी गला कसकर पत्नी की हत्या कर दी और शव छोड़कर फरार हो गया। मंगलवार सुबह घटना का पता चला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल भेज दिया। पास मिले आधार कार्ड से मृतका की पहचान भोरे निवासी श्यामा फुलवा देवी (35) के रूप में की गई।

किराए के मकान में रहते थे पति-पत्नी- थानाध्यक्ष शशि कुमार राणा ने बताया कि पति-पत्नी बैदनाथ सहाय लेन में भाड़े के मकान में कई माह से रह रहे थे। उसके पति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। लेकिन कुछ लोग बताते हैं उसके पति का नाम शिवा पासवान है। वह उसरी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। चर्चा है कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था। उनके बच्चे नही थे। पति ट्रक चलाकर परवरिश कर रहा था।

सुबह कमरे में देखा तो बेड पर पड़ा था महिला का शव-मकान मालिक महेंद्र साव ने पुलिस को बताया कि सोमवार शाम में आम दिनों की तरह उनके घर में खाना पका। तब तक दोनों में कोई विवाद नहीं दिख रहा था। देर शाम दोनों में किसी बात को लेकर नोकझोंक होने लगी। हमलोग क्या जानें की नोकझोंक होते-होते मामला इतना तक पहुंच जाएगा। हालांकि हम लोगों ने इसे सामान्य ही समझा। सुबह काफी देर तक उनका कमरा नहीं खुला। कोई आवाज नहीं आई तो अंदर जाकर आवाज लगाई। लेकिन कोई आवाज नहीं आई । तब जाकर कमरे में झांककर देखा तो बेड पर महिला मृत पडी थी। घटना को अंजाम देकर उसका पति फरार था। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। उसके स्वजनों से संपर्क का प्रयास किया जा रहा है। थानेदार ने कहा कि आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे यूपी के मंत्री, अधिकारियों की टीम भी करेगी समन्यवय

लखनऊ । उत्तराखंड के चमोली में आपदा की जद में आए ऋषिगंगा और तपोवन-विष्णुगाड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम रहे रहे लापता श्रमिकों व कार्मिकों की खोज के साथ वहां पर राहत कार्य को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन मंत्रियों का समूह भेजा है। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी के नेतृत्व में प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों की टीम उत्तराखंड शासन के साथ समन्वय करेगी।

उत्तराखंड में बड़ी आपदा में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद चिंतत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश के नागरिकों सहित सभी प्रभावितों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। इसके दृष्टिगत उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से दूरभाष पर वार्ता कर उनको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया है।

योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तराखंड की बड़ी आपदा में राहत कार्य में मदद देने के लिए कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी व बाढ़ राहत राज्यमंत्री विजय कश्यप को उत्तराखंड भेजा है। यह मंत्री त्तराखंड में हादसे वाली जगह का दौरा करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार से सम्पर्क करके आपदा पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराएंगे।

इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड शासन और प्रशासन से समन्वय स्थापित करने के लिए अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम बनाई है। वहां पर फंसे लोगों की सहायता के लिए लखनऊ में राहत आयुक्त कार्यालय में 24 घंटे

संचालित रहने वाला कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिसका नंबर हेल्पलाइन नम्बर 1070 है। लखनऊ में राहत आयुक्त कार्यालय में राज्य स्तरीय इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को क्रियाशील कर दिया गया है। प्रदेश के लापता व्यक्तियों के परिजन लापता व्यक्ति का विवरण राहत हेल्पलाइन-1070 व व्हॉट्सएप नंबर 9454441036 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही आपदा प्रभावित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भी कंट्रोल रूम स्थापित हैं। जहां प्रशासन, पुलिस और सिंचाई विभाग के कर्मचारी 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक कंट्रोल रूम हरिद्वार में भी स्थापित किया गया है। चमोली के पावर प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के श्रमिक व कार्मिक कार्य कर रहे हैं। इनमें से कई लापता है, जबकि कुछ के शव मलवे में मिले हैं। ऐसे में अपने स्वजनों को लेकर संबंधित परिवारों में चिंता बनी हुई है।

मृतक आश्रितों को दो-दो लाख- सीएम योगी आदितत्यनाथ ने चमोली हादसे में मृत प्रदेश के लोगों के आश्रितों को दो-दो लाख रुपया मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक के मदद रूप में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

इसके साथ घायलों के लिए समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। आपदा से प्रभावित हुए प्रदेश के परिवारों की सहायता के लिए राहत आयुक्त कार्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित है। उत्तराखंड सरकार से समन्वय के लिए प्रदेश सरकार के दो अधिकारियों को देहरादून भेजा गया है।

उत्तराखंड में फंसे मेरठ के युवक ने बताई आपबीती- उत्तराखंड त्रासदी के दौरान लापता हुए मेरठ के युवकों की सुरिक्षत लोकेशन सोमवार रात मिल गई थी लेकिन स्वजन परेशान थे कि उनसे बात नहीं हो पा रही। इनमें चार मेरठ, पांच अमरोहा व एक बिजनौर का युवक है। मंगलवार सुबह 11-30 बजे उत्तराखंड से जब एक युवक ने स्वजन को फोन किया तो घर का माहौल बदल गया। युवक ने बताया कि वह सुरक्षित तो हैं लेकिन अभी रैनी गांव के पास फंसे हुए हैं।

वहां फंसे रोहित प्रजापति के रिश्तेदार सोमपाल ने बताया कि मंगलवार सुबह उनके मोबाइल पर रोहित का फोन आया। रोहित ने कहा कि वह सभी रैनी गांव में फंसे हुए हैं। सभी सुरक्षित हैं, लेकिन उनके पास सोमवार शाम से खाने के लिए कुछ नहीं है। जिस कारण वह परेशान हैं।

बड़ी उलझन में आया पुलिस महकमा, कौन थे सीओ बृज सिंह नहीं है कोई रिकॉर्ड

कानपुर । बिकरू कांड में पुलिस की उलझने कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एसआइटी जांच में आरोपित अनाम सीओ पुलिस महकमे के लिए बवाल-ए-जान हो गया है। लंबी कवायद के बाद बमुश्किल बृज सिंह का नाम पता चला लेकिन पुलिस मुख्यालय के पास इस नाम के सीओ का कोई रिकार्ड मौजूद नहीं है। ऐसे में सीओ स्तर की जांच पूरी होने में देरी हो सकती है।

जांच में सामने आए थे 11 सीओ के नाम

वरिष्ठ आइएएस संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में गठित एसआइटी ने 11 सीओ और 37 गैर राजपत्रित पुलिसकर्मियों की भूमिका पर सवाल उठाए थे। सीओ स्तर के अधिकारियों की जांच एसपी पश्चिम डॉ. अनिल कुमार को मिली थी। इसमें से एक सीओ प्रोन्नत होकर आइपीएस हो चुके हैं। इनके खिलाफ हो रही जांच अब डीआइजी डॉ. प्रीतिंदर सिंह कर रहे हैं, जबकि बाकी बचे दस सीओ स्तर के अधिकारियों में एक का नाम न होकर केवल तैनाती समय का जिक्र था। लंबी छानबीन के बाद बताया गया कि उनका नाम बृज सिंह है। नाम के सत्यापन के लिए फाइल पुलिस मुख्यालय भेजी गई थी।

सीओ का रिकार्ड न मिलने से अटकी जांच

एसपी पश्चिम डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि मुख्यालय से उन्हें मौखिक जानकारी दी गई है कि इस नाम से किसी सीओ का रिकार्ड विभाग के पास नहीं है। ऐसे में जांच लटक गई है। गौरतलब है कि उक्त अनाम सीओ से 12 जुलाई 1997 व 24 जुलाई 1997 को विकास दुबे के भाई दीपू दुबे और अविनाश दुबे के शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किए थे। अविनाश दुबे की मृत्यु हो चुकी है।

नहीं मालूम थे दो सीओ के नाम

एसआइटी की जांच में चिह्नित 11 सीओ में दो के नाम नहीं पता था। 24 जुलाई 1997 को नियुक्त तत्कालीन सीओ बिल्हौर और 12 जुलाई 1997 को नियुक्त तत्कालीन सीओ रसूलाबाद की नियुक्ति के नाम पता नहीं चल पाए थे। बाद में एक सीओ के नाम की जानकारी मिली तो बिल्हौर में उस समय बृज सिंह के नाम से सीओ कार्यरत थे। इसके बाद उनका रिकार्ड पता करने के लिए पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजा गया था।

मंत्रिमंडल विस्तार से पहले भाजपा में घमासान, विधायक ज्ञानेंद्र ने फूंका बगावत का बिगुल

पटना । बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के पहले ही भाजपा में जमकर घमासान हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट के पहले विस्तार में जगह नहीं मिलने से भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू खफा हैं। डिप्टी सीएम पद पर सवर्णों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। कहा है कि भाजपा ने दो-दो उप मुख्यमंत्री बनाया लेकिन सवर्ण समाज को एक भी पद नहीं दिया।

उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। ज्ञानू ने पार्टी नेतृत्व को चेतावनी दी है। भाजपा पर राजपूत और सवर्ण समाज के साथ वरिष्ठ विधायकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। ज्ञानू ने अपने साथ 15 विधायकों के होने का दावा किया है। कहा कि समय आने पर फैसला करेंगे। भाजपा गंभीर परिणाम भुगतेगी।

वरिष्ठों की अनदेखी का आरोप-

बकौल ज्ञानू, कैबिनेट विस्तार में भाजपा ने जाति, क्षेत्र और छवि का ख्याल भी नहीं

रखा। कैबिनेट विस्तार में अपराधियों जगह दी गई है। सवर्णों की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि लगता है कि भाजपा को सवर्णों का सिर्फ वोट चाहिए। सत्ता में दूसरे को तरजीह दी जा रही है। मंत्रियों की सूची देखकर लगा कि भाजपा में अनुभवी और वरिष्ठ होना गलत है। नंद किशोर यादव, विनोद नारायण झा, प्रेम कुमार और राम नारायण मंडल सरीखे नेताओं की जगह क्या तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी से पार्टी को ताकत मिलेगी

नतीजा भुगतने की चेतावनी-

मगध क्षेत्र में भूमिहारों की उपेक्षा हुई है। कैबिनेट में पूरे शाहाबाद और मगध क्षेत्र से एक भी भूमिहार को नहीं लिया है। मिथिलांचल में ललित नारायण एवं जगन्नाथ मिश्र की पहचान प्रतिष्ठा नीतीश मिश्र को मंत्री नहीं बनाकर अनदेखी की गई है। पार्टी को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। बता दें कि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से ज्ञानू लगातार चौथी बार 17वीं विधानसभा चुनाव में विधायक चुने हैं। बाढ़ में आजादी के बाद दो बार से ज्यादा लगातार कोई विधायक नहीं जीत पाया।

योगी सरकार 22 फरवरी को पेश करेगी बजट, 5.6 लाख करोड़ रुपये के आकार का अनुमान

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट विधान मंडल में 22 फरवरी को पेश करेगी। यह योगी सरकार का पांचवां और आखिरी पूर्ण बजट होगा। विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बजट 22 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। वर्ष 2022 का प्रथम सत्र होने के नाते 18 फरवरी को पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देंगी।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में बुनियादी ढांचे पर फोकस होगा। चुनावी वर्ष का बजट होने के नाते सरकार इसके जरिये विभिन्न वर्गों को भी साधने की कोशिश करेगी। हालांकि कोरोना आपदा के कारण राज्य और केंद्र सरकार के राजस्व में आई कमी से बजट के लिए संसाधन जुटाने की चुनौती बढ़ गई है। सरकार के पिछले बजट का आकार 5.12 लाख करोड़ रुपये था। कयास लगाये जा रहे हैं कि बजट का आकार 5.5 से 5.6 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। हालांकि चुनावी वर्ष में हौसला दिखाते हुए सरकार इससे बड़े आकार का बजट भी प्रस्तुत कर सकती है। चुनावी वर्ष में अपनी हसरतों को परवान चढ़ाने के लिए सरकार अगस्त और दिसंबर में दो अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है।

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी की नजर योगी सरकार के अगले बजट पर है। ऐसे में इस बजट को सबसे खास बनाने की कोशिश है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में योगी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले के इस बजट को सबसे खास बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि यह बजट नए रूप में पेश किया जा सकता है। इसमें हर गांव, घर, परिवार की बात होगी तो उद्यमी, किसान, महिला, नौजवान की चिंता भी नजर आएगी। व्यापारी और बेरोजगार के लिए कुछ खास होगा तो बेसहारा की सहारा बनने वाली कोई न कोई सौगात भी संभव है।

माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह चुनावी बजट भी होगा। अगले बजट के जरिए सरकार अपने चुनावी समीकरण साधने की कोशिश करेगी। विधानमंडल का पिछला बजट सत्र अगस्त में हुआ था। दिसंबर में शीत कालीन सत्र बुलाए जाने और इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुपूरक बजट पेश किये जाने की चर्चा थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण संसाधनों की तंगी से जूझ रही प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अंतत- बजट सत्र नहीं बुला सकी थी।

बिजनौर पुलिस के हत्थे चढ़ा पांचवां हत्यारोपित, भरे बाजार में युवक को मारी थी गोली

बिजनौर । रचित हत्याकांड में सोमवार को पांचवां हत्यारोपित भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उस पर 50 हजार रुपये का इनाम था। वह आत्मसमर्पण की फिराक में था। बताया जा रहा है कि परिवार से मिलने के लिए घर आया था। तभी भनक लगने पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपित से पूछताछ की जा रही है। उधर, एहतियात के तौर पर कस्बे में पुलिस-पीएसी तैनात है। मृतक के घर पर पुलिस का पहरा है।

पांच फरवरी को शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव स्योहारा गिरधर निवासी रचित पुत्र बबलू की हल्दौर थाना क्षेत्र के कस्बा झालू के साप्ताहिक बाजार में दूसरे संप्रदाय के पांच युवकों ने गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। एक आरोपित आसिफ अब्दी फरार चल रहा था। इस प्रकरण में थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज समेत सात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। फरार आसिफ पर एसपी ने 25 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की थी। आइजी ने 50 हजार रुपये इनाम की संस्तुति पर मुहर लगा दी थी।

पुलिस की चार टीमें आसिफ की तलाश में लगी थी। पुलिस की घेराबंदी के बाद सोमवार को नाटकीय ढंग से आरोपित घर से दबोच लिया गया। पुलिस की टीम पहुंचते ही आरोपित सोशल मीडिया के लोग भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने उसे घर से हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। वहीं एहतियात के तौर पर कस्बे में पुलिस मुस्तैद है। लगातार पुलिस गश्त कर रही है। मृतक रचित के घर पर भी पुलिस बल तैनात है।

असलहा बरामद करना चुनौती

आसिफ अपने घर से गिरफ्तार हुआ है। उसने वारदात के समय पिस्टल का इस्तेमाल किया था। बताया जा रहा है कि पिस्टल से रचित पर फायर किया था। आसिफ अब्दी ने असलहे को छिपा दिया है। पुलिस की टीम पूछताछ के आधार पर असलहा बरामद करने के प्रयास में लगी है। पूछताछ के बाद पिस्टल बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। हथियार बरामद करना पुलिस के लिए एक चुनौती है। चूंकि तीन दिन की फरारी के दौरान आरोपित ने असलहा गोपनीय जगह छिपा दिया होगा, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पुलिस के लिए यह बरामदगी मुश्किल हो सकती है।

पूछताछ में खुल सकते हैं राज

आसिफ से पूछताछ के बाद आरोपित से अहम सुराग मिलने के आसार हैं। हत्याकांड के पीछे कोई और साजिश तो नहीं है, इसकी पड़ताल भी की जा रही है। पुलिस आसिफ को घर से बुलाने वाले दो युवकों की भी तलाश कर रही है। उनसे पूछताछ की जाएगी कि रचित के साथ आने के पीछे कोई साजिश तो नहीं है। वहीं आसिफ से पूछताछ में भी आवश्यक जानकारी मिलेगी।

फिरोजपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा की गाड़ी पर हमला, बैरिकेडिंग तोड़ पहुंचे किसान

फिरोजपुर। पंजाब में भाजपा नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। फिरोजपुर में किसानों ने एक बार फिर पार्टी के पंजाब प्रधान अश्वनी शर्मा की गाड़ी पर हमला किया। हालांकि पुलिस हमले की बात को नकार रही है। अश्वनी शर्मा नगर कौंसिल चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने मालवाल रोड स्थित सिटी प्लाजा पहुंचे थे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचने की सूचना पर किसानों ने पहले से ही पैलेस के बाहर धरने पर बैठे थे। अश्वनी शर्मा के पहुंचने पर किसानों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को हटा दिया। इस दौरान पुलिस ने किसानों पर हल्का बल भी प्रयोग किया। किसानों ने भाजपा के पूर्व विधायक सुखपाल सिंह नन्नू की पगड़ी भी उतारने की कोशिश की। किसान नेता हरनेक सिंह मेहमान ने कहा कि हमला करने वाले किसान नहीं थे, बल्कि यह असामाजिक तत्व थे। वहीं, पुलिस ने शर्मा की गाड़ी पर हुए हमले से इन्कार किया है।

बता दें, गत दिवस नवांशहर में भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा के कार्यक्रम का किसानों ने विरोध किया था। हंगामे को देखे हुए अश्वनी शर्मा ने कार्यक्रम रद कर दिया। इसके बाद उन्होंने नंगल में कहा कि कांग्रेस किसान आंदोलन का गलत फायदा उठा रही है। अश्वनी शर्मा के आने की सूचना मिलते ही किसान नारेबाजी करते हुए पंडोरा मोहल्ला पहुंच गए। यहां पुलिस और किसानों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।

सांपला के काफिले पर भी हुआ था हमला- गत दिवस मोगा में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को भी किसान यूनियन के विरोध का सामना करना पड़ा था। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का छकाते हुए दिल्ली भाजपा के करोल बाग के जिलाध्यक्ष भारत भूषण की कार के शीशे तोड़ दिए। यहां पुलिस व प्रदर्शनकारियों की तीखी झड़प हुई। विरोध को देखते हुए सांपला ने अपना दौरा बीच में ही छोड़ दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़कर मंत्री का काफिला निकाला। सांपला को यहां चुनावी सभा को संबोधित करना था।

एक बार फिर मंगलवार का दिन सुमित के लिए हुआ मंगलकारी, बन बए मंत्री

जमुई । मंगलवार का दिन एक बार फिर चकाई के निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह के लिए मंगलकारी साबित हुआ। इसके पहले चुनाव परिणाम भी मंगलवार को आया था और वह रोचक मुकाबले में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। इधर चकाई विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक सुमित कुमार के मंत्री पद की शपथ लेते ही उनके पैतृक गांव पटरी सहित जमुई में जश्न का माहौल काम हो गया। खासकर सुमित समर्थकों के बीच इस युवा नेता की ताजपोशी से भविष्य की राजनीति में कद बड़ा होने से जोड़कर देखा जा रहा है।

गौरतलब हो कि 39 वर्षीय सुमित कुमार सिंह दूसरी बार चकाई विधानसभा से विधायक बने हैं। इसके पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर चकाई से 2010 में निर्वाचित हुए थे। 2015 में महागठबंधन की प्रत्याशी सावित्री देवी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2020 में एक बार फिर वह जदयू के टिकट से वंचित हुए और

चुनाव मैदान में निर्दलीय कूद पड़े। लेकिन चकाई की जनता ने उन्हें विधानसभा का टिकट थमाते हुए संघर्षपूर्ण मुकाबले में जीत का माला दिया। परिणाम आने के बाद सुमित ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में आस्था व्यक्त करते हुए सरकार बनाने में समर्थन देने की घोषणा की थी। इसके बाद से ही उनके मंत्री बनने के कयास लगाए जाने लगे थे। सुमित आरपीएस इंटर कॉलेज से इंटर तक की पढ़ाई के बाद जेएनयू के विद्यार्थी रहे हैं। ग्रेजुएट सुमित जमुई सहित आसपास के जिलों में युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं।

इंटरनेट मीडिया पर इनकी सक्रियता खूब रहती है। इसके साथ ही क्षेत्र में जनता के सुख दुख का सहभागी बना रहना इनकी खासियत है। यही वजह है कि 2010 में झारखंड मुक्ति मोर्चा तथा 2020 में निर्दलीय जीत दर्ज कराने में कामयाब हुए। 2015 में भी निर्दलीय ही मैदान में कूदे थे और निर्वाचित महागठबंधन प्रत्याशी सावित्री देवी के निकटतम प्रतिद्वंदी रहे थे। यहां यह बताना लाजिमी है कि सुमित पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के पुत्र तथा स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह के पौत्र हैं। लिहाजा राजनीति इन्हें विरासत में मिली है। लेकिन, जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की इनकी कर्मठता इन्हें औरों से अलग खड़ा करता है।

एक नजर

देशभर में बंद पड़े विश्वविद्यालय और कॉलेज जल्द खुलेंगे, यूजीसी ने दी हरी झंडी

नई दिल्ली । कोरोना वायरस के घटते प्रभाव को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देशभर में बंद पड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जरूरी सुरक्षा इंतजामों के साथ फिर खोलने के लिए कहा है। हालांकि, इन्हें कब से खोलना है, इसका फैसला उन्हें राय सरकार और स्थानीय प्रशासन की सहमति के आधार पर करने को कहा है। यूजीसी ने फिलहाल इस संबंध में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को पूरी स्वतंत्रता दी है। साथ ही संस्थानों को खोलने के लिए पूर्व में जारी गाइडलाइंस पर अमल सुनिश्चित करने को भी कहा है। यूजीसी ने यह कदम बंद पड़े विश्वविद्यालयों और दूसरे उच शिक्षण संस्थानों को खोलने की छात्रों की मांगों को देखते हुए लिया है। हालांकि, इसे लेकर यूजीसी पूरी तरह से सतर्क भी है, क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र और केरल जैसे रायों में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहां हर दिन हजारों की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में यूजीसी बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं है और न ही संस्थानों पर इन्हें खोलने के लिए कोई दबाव ही बनाया है। संस्थानों को अपनी सुविधा और तैयारियों के आधार पर छात्रों को बुलाने से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार दिया है। वहीं, यूजीसी की संस्थानों को खोलने से जुड़ी गाइडलाइंस में इस बात पर जोर दिया गया है कि ऑफलाइन कक्षाएं जब शुरू हों तो छात्रों को एक सीट छोड़कर बैठाया जाएगा। साथ ही मास्क पहनने और बार-बार हाथ साफ करने को अनिवार्य बनाया जाए।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोलने को लेकर यूजीसी ने यह कदम इसलिए भी उठाया है, क्योंकि यादातर रायों में स्कूल खुल गए हैं। हालांकि, उनमें अभी सिर्फ नौवीं से बारहवीं तक के बचों को बुलाया जा रहा है। बावजूद इसके सभी छात्र अभी स्कूल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल आने को अभी अनिवार्य नहीं किया गया है। साथ ही अभिभावकों की अनुमति भी जरूरी की गई है। मालूम हो कि स्कूलों के साथ ही देशभर के उच शिक्षण संस्थानों को भी कोरोना की दस्तक के साथ ही पिछले साल मार्च में बंद कर दिया गया था, जो अभी भी बंद हैं।

राजस्थान के राजसमंद में वेलर्स से साठ लाख की लूट, नौ सौ ग्राम सोना, बीस किलो चांदी लूटी

उदयपुर । राजसमंद जिले के खमनोर थाना क्षेत्र के शिशोदा गांव में बीती रात एक वेलर्स के साथ साठ लाख रुपए से अधिक के जेवरात और नकदी लूट की घटना सामने आई है। तीन बाइकों से आए छह नकाबपोश बदमाशों ने वेलर्स से नौ सौ ग्राम सोना तथा बीस किलो चांदी के जेवरात के साथ पैंसठ हजार रुपए की नकदी भी लूट लिए। जिले में लूट की यह घटना अब तक की सबसे बड़ी बताई जा रही है। पुलिस ने पांच से अधिक अपराधियों के शामिल होने पर डकैती का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। पुलिस इस घटना में किसी जानकार का हाथ होने की संभावना को लेकर जांच में जुटी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि राजसमंद जिले के शिशोदा गांव से गायत्री वेलर्स का मालिक कमलेश सोनी सोमवार रात दुकान बंद कर अपने घर लौट रहा था कि रास्ते में लूट की यह घटना हुई। कमलेश सोनी की शिशोदा बावजी मंदिर के पास दुकान है और वह रोजाना की तरह जेवरात और नकदी अपने घर ले जा रहे थे। दुकान से लगभग तीन सौ मीटर की दूरी पर पुलिया के समीप एक बाइक पर आए दो बदमाशों ने पहले उन्होंने रोका तथा बाइक सहित गिरा दिया। इसके बाद अन्य दो बाइकों से चार बदमाश और आए और वेलर से मारपीट कर जेवरात और नकदी से भरा बैग छीनकर भाग निकले। बदमाश अपने साथ चाकू लिए हुए थे और उनसे संघर्ष के दौरान जेवरात व्यापारी की अंगुली भी कट गई। बदमाशों के फरार होने पर व्यापारी गिरता-पड़ता ग्रामीणों के पास पहुंचा और उनके जरिए पुलिस को घटना का पता चला।

सभी बदमाश 25 से तीस साल के- पीड़ित वेलर व्यापारी कमलेश सोनी ने पुलिस को बताया बदमाश पचीस से तीस साल के बीच के उम्र के थे और सभी हिन्दी में बात कर रहे थे। खमनोर थानाधिकारी कैलाश सिंह का कहना है कि लूट में स्थानीय तथा जानकार बदमाश शामिल हो सकते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि बदमाश शिशोदा तथा आसपास क्षेत्र के हो सकते हैं। इसलिए वह मुख्य रास्तों की जगह अंदरूनी रास्तों से भागे हैं। हालांकि जिन मार्गों पर सीसीटीवी लगे हैं, उनके फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव का कहना है कि अपराधियों की तलाश के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया हुआ है। घटना की वास्तविकता की जांच कर जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा।

नवी मुंबई के तलोजा इलाके में कैमिकल फैक्टरी में आग, आसमान में फैला काले धुएं का गुबार

मुंबई । महाराष्ट्र के नवी मुंबई में तलोजा इलाके में एक कैमिकल फैक्टरी में मंगलवार दोपहर भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल के कई वाहन आग बुझाने के लिए मौके पर रवाना हो चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आग लगने के कारण के संबंध में अभी जानकारी नहीं मिल पायी है, इस मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। बता दें कि आग 34 नंबर प्लांट में दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर लगी थी। फैक्टरी में रखे ज्वलनशील रसायन के कारण देखते ही देखते ही फैल गई और आसमान में काले धुएं का गुबार नजर आने लगा। ड्रम में रसायन भरा होने के कारण धमाका हो रहा है जो कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रहा है। अगर जल्द आग पर काबू नहीं पाया गया तो काफी ज्यादा नुकसान की आशंका है।

गौरतलब है कि बीते तीन दिन पहले मुंबई के मानखुर्द इलाके में दोपहर 2 बजकर 45 मिनट पर कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई थी। आग लगते ही काले धुएं का गुबार आसमान में चारों तरफ फैल गया था। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि उस पर काबू पाने के लिए दमकल के 19 वाहन मौके पर पहुंच गए थे। एहतियातन आसपास के इलाकों को भी खाली करवा लिया गया था। बता दें कि मुंबई से अक्सर आग लगने की खबरें आती रहती हैं, इन आगजनी की घटनाओं से अब तक काफी जानमाल का नुकसान हो चुका है।

महाराष्ट्र में 3,062 निजी बसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, परिवहन विभाग ने 12 घंटे चलाया विशेष अभियान

मुंबई । महाराष्ट्र के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) ने सुरक्षा नियमों और अन्य मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए 3,000 से अधिक निजी बसों के खिलाफ कार्रवाई की है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को बताया कि पिछले सप्ताहांत में परिवहन विभाग द्वारा शुरू किए गए 12 घंटे के विशेष अभियान के दौरान निजी बसों को कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

राज्य परिवहन आयुक्त अविनाश धाकने ने यहां अपने कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनके विभाग ने सुरक्षा नियमों और अन्य मानदंडों के उल्लंघन के लिए 3,062 निजी बसों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें से 213 बसों को विशेष अभियान के दौरान हिरासत में लिया गया था, जो शनिवार शाम और रविवार सुबह के बीच चलायी गयी थी। ढाकने ने कहा कि यह अभियान एक बस दुर्घटना के बाद किया गया था जिसमें शामिल निजी वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त हो चुका था। यह दुर्घटना हाल ही में मुंबई-गोवा राजमार्ग पर व्यस्त कश्मीरी घाट पर हुई थी। उन्होंने कहा कि विभाग यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में इस तरह के सरप्राइज चेक करता रहेगा। महाराष्ट्र मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने ड्राइव के दौरान 3,062 वाहनों को ज्ञापन (मेमो) जारी किए हैं। इनमें से 213 वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र की समाप्ति, परमिट के बिना संचालन और सड़क कर का भुगतान न करने सहित विभिन्न उल्लंघनों के लिए हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि अधिकतम हिरासत में लिए गए वाहन ठाणे आरटीओ के अधिकार क्षेत्र में थे, उन्होंने कहा कि विभाग ने कई नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पंजीकृत बसों को महाराष्ट्र में उचित यात्री गाड़ी परमिट के बिना जब्त कर लिया। ढकाने ने कहा कि उन्होंने इसे प्रभावी बनाने के लिए अभियान के बारे में अत्यंत गोपनीयता बनाए रखी और विभिन्न रैंकों के 600 से अधिक अधिकारियों ने ऑपरेशन में भाग लिया। विभाग ने निजी वाहनों में यात्रियों को फेरी लगाने के लिए राज्य परिवहन की बसों की व्यवस्था की थी जिसमें वे यात्रा कर रहे थे जिन्हें सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के लिए हिरासत में लिया गया था। महाराष्ट्र में 50 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हैं। राज्य परिवहन आयुक्त ने कहा इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह जांचना था कि यात्रियों के सफर के लिए बसें फिट थीं या नहीं।

भाजपा ने किया चुनाव अभियान का श्रीगणेश, प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल ने लांच किया थीम सॉन्ग

अहमदाबाद । गुजरात में भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक जोरदार चुनाव अभियान का श्रीगणेश किया है। किसी फिल्म की लॉन्चिंग की तरह चुनाव के लिए एक थीम सॉन्ग ÷शहर-शहर, गांव-गांव भाजपा की लहर÷ को खुद प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल ने लांच किया। इसके अलावा 40 लघु फिल्म एक 1 मिनट की तथा 20 बड़ी फिल्में नई डिजाइन के 21 होर्डिंग?स तथा 19 जीआईएफ भी इस चुनाव के लिए जारी की गई है ताकि चुनावी माहौल को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया जा सके। चुनावी डिबेट में टीवी चैनलों के ऊपर भाजपा के प्रवक्ता लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं तथा कांग्रेस पर इस चुनाव में भी टिकट वितरण में मनमानी करने तथा टिकट बेचे जाने के आरोपों को भी उछाल रहे हैं।

सी आर पाटिल ने बनायी खास रणनीति - भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सी आर पाटिल ने प्रदेश भाजपा कार्यालय श्रीकमलम पर मीडिया तथा चुनाव प्रचार का काम देख रहे लोगों के साथ बैठक कर एक खास रणनीति बनाई है ताकि इस चुनाव में शहर से लेकर गांव तक कांग्रेस पर हावी रहा जा सके। भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। सीआर पाटील एक बयान जारी कर कांग्रेस को विकास विरोधी, राम मंदिर निर्माण को उलझाने तथा भटकाने वाली तथा मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टी बताया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में कांग्रेस अंधी हो चुकी है - पाटिल का आरोप है कि ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे पर कांग्रेस ने है

संवेदनशील रुख अख्तियार किया। कांग्रेस की मानसिकता को पाटिल ने देश विरोधी करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में कांग्रेस अंधी हो चुकी है तथा उसे देश हित की भी कोई परवाह नहीं है। पाटिल कांग्रेस पर गुजरात विरोधी होने का भी आरोप लगाया, इनका कहना है कि सरदार सरोवर बांध के निर्माण तथा नर्मदा नहर योजना को लेकर कांग्रेस हमेशा बाधाएं उत्पन्न करती रही। नर्मदा में बनाई गई विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को कांग्रेस नेता तथा विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता परेश धनानी ने कबाड़ बता कर लौह पुरुष सरदार पटेल का अपमान किया।

लोगों की भावनाओं के प्रति कांग्रेस कतई जागरूक नहीं

पाटिल का कहना है कि कांग्रेस एक परिवार वादी पार्टी बनकर रह गई है देश के विकास देश की संस्कृति तथा लोगों की भावनाओं के प्रति कांग्रेस कतई जागरूक नहीं है। बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता यमल व्यास तथा मीडिया संयोजक यग्नेश दवे, सह संयोजक किशोर मकवाना, प्रचार संयोजक महेश कासवाला, अतुल भावसार आदि नेता मौजूद थे। पाटिल ने अपनी मीडिया टीम को भाजपा के चुनाव प्रचार की रणनीति तथा स्लोगन वह थीम सॉन्ग आदि की जानकारी दी। भाजपा निकाय चुनाव को लेकर के काफी गंभीर है पार्टी आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर निचले स्तर तक संगठन में बड़ा बदलाव किया है साथ ही चुनाव से पहले संगठन को गांव-गांव गली-गली तथा घर-घर तक पहुंचाने के लिए पेज प्रमुख तथा पन्ना समितियों का भी गठन किया है।

कांग्रेस नेताओं में असंतोष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में रहते पन्ना प्रमुख की शुरुआत की थी अब सांसद सी आर पाटिल ने पन्ना समितियों का गठन कर भाजपा के संगठन को और गहराई तक काट दिया है। गुजरात में भाजपा की जड़ें गहरी करने में पन्ना प्रमुख तथा पन्ना समितियों का काफी योगदान है। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा, नेता विपक्ष परेश धनानी, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल तथा गुजरात कांग्रेस के प्रभारी राजीव सातव पिछले कई महीनों से लगातार दौड़-धूप करके संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ऐन चुनाव से पहले टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस के नेताओं में बड़े पैमाने पर असंतोष उभर कर सामने आया है। हालांकि कांग्रेस ने बचते बचाते अपने प्रत्याशियों को भी फोन पर ही सूचित कर नामांकन भरवा दिया है लेकिन स्थानीय नेताओं में चल रहा असंतोष चुनाव परिणामों पर विपरीत असर डाल सकता है।

बीजेपी विधायक ने सवाल पूछने पर मीडियाकर्मी को धमकाया, कहा- एक और सवाल पूछा तो पहले पीटूंगा फिर तुझे यहीं पर निपटा दूंगा

वड़ोदरा । अपने विवादित बयानों से चर्चा में बने रहने वाले वडोदरा से भाजपा विधायक मधु श्रीवास्तव अब एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वे एक पत्रकार को लाइव कैमरे पर धमकी देने के चलते विवादों में घिर गए हैं।

बता दें कि, आने वाले कुछ दिनों में नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और विधायक के बेटे दीपक श्रीवास्तव चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया कि, आपके बेटे की तो तीन संताने हैं तो वह नगर निकाय का चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? ऐसे में निकाय चुनाव में उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। यह सवाल सुनते ही भाजपा विधायक झल्ला उठे और लाइव कैमरे पर धमकी देते हुए कहा- एक और सवाल पूछा तो पहले पीटूँगा फिर तुझे यहीं पर निपटा दूंगा।

इसके बाद विधायक यहीं नहीं रुके, उन्होंने पत्रकार से कहा- मेरे बेटे दीपक के केवल दो बचे हैं। यदि तुम्हारे पास तीन संतानों के पुख्ता प्रमाण हैं तो मुझे दो नहीं तो बकबक करने से पहले जानकारी सही करो। और यादा बकवास नहीं करना। साथ ही कहा कि, मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा और जहाँ तक रही बात नामांकन रद्द करने की तो वह चुनाव अधिकारियों का काम है।

ज्ञात हो कि करीब एक साल पहले भी बीजेपी रूरसवाल पूछने को लेकर पत्रकार पर गुस्सा उठे थे। साथ ही सरेआम पत्रकार को गालियां देकर कैमरा भी छीन लिया था।

स्वयंसेवक मुंबई के एनसीपीए नरीमन पॉइंट में जन्मजात हृदय दोष जागरूकता सप्ताह के अवसर पर एक वाकथॉन में भाग लेते हुए।

रंजन गोगोई को लेकर महुआ मोइत्रा की टिप्पणी पर सरकार गंभीर, संसदीय कार्य मंत्री ने कही कार्रवाई पर विचार की बात

नई दिल्ली । तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने सोमवार को लोकसभा में राम मंदिर पर सीजेआई रंजन गोगोई के फैसले को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। इस मामले पर अब संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के फैसले और तत्कालीन सीजेआई पर अभद्र टिप्पणी करना एक गंभीर विषय है। इसको लेकर तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा पर उचित कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है।

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा ने उचतम न्यायालय के एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश को लेकर एक टिप्पणी की। इसका भाजपा सदस्यों और सरकार की ओर से विरोध किया गया। संसदीय कार्य राय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताई और कहा कि इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया जा सकता। वहीं, भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने नियमों का हवाला देते हुए इस पर आपत्ति व्यक्त की।

इस पर पीठासीन सभापति एन के प्रेमचंद्रन ने कहा कि अगर महुआ मोइत्रा की बात में कुछ आपत्तिजनक पाया जाता है तो उसे रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा। मोइत्रा ने कहा था कि न्यायपालिका अब पवित्र नहीं रह गयी है। उन्होंने इसके बाद उचतम न्यायालय के एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश को लेकर विवादित टिप्पणी की। तृणमूल कांग्रेस सदस्य ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग सत्ता की ताकत, कट्टरता, असत्य को साहस कहते हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने दुष्प्रचार और गलत सूचना फैलाने को कुटीर उद्योग बना लिया है। मोइत्रा ने कहा कि इनकी (सरकार की) सबसे बड़ी सफलता कायरता को साहस के रूप में परिभाषित करना है।

तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस सरकार ने एकतरफा ढंग से नागरिकता संशोधन कानून बनाने का काम किया लेकिन काफी समय गुजर जाने के बाद भी इसके नियमों को अधिसूचित नहीं कर पायी। अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2020 में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश रहा।

उन्होंने दावा किया कि दो वर्षों तक अर्थव्यवस्था में वृद्धि नहीं होगी। तीन विवादित कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए मोइत्रा ने कहा कि सरकार कृषि कानून लाई जबकि विपक्ष और किसान संगठन इन्हें किसान विरोधी बता रहे थे। उन्होंने कहा कि इन्हें बिना आम-सहमति और बिना समीक्षा किये लाया गया तथा बहुमत के बल पर लाया गया। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा कि वह केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी से पूछना चाहती हैं कि क्या इस तरह से लोकतंत्र चलेगा, क्या एक पार्टी का शासन देश में चलेगा।

कोरोना वायरस से भारत को लगातार राहत, दैनिक मौतों में दिखी 55 प्रतिशत की गिरावट

नई दिल्ली । भारत समेत दुनिया भर के 190 से यादा देश कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित हैं। हालांकि अब भारत समेत कई देश इससे उबरने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक महीने में कोरोना वायरस की औसत दैनिक मौतों में 55त्न की गिरावट आई है।

कोरोना के दैनिक आंकड़ों में कमी राहत दे रही है। कुल मामलों की बात करें तो 1,08,47,304 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 1,05,48,521 लोग ठीक हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 1,55,158 हो चुकी है। इसके अलावा 1,43,625 मामले अभी सक्रिय हैं। अब तक 62,59,008 लोगों को टीका लगाया जा चुका है।

इधर, कोरोना से लड़ने के लिए भारत अब पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन भेजकर मदद कर रहा है। इसे भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी माना जा रहा है। रविवार को अफगानिस्तान में भारत से भेजी गई वैक्सीन की पहली खेप पहुंची है। भारत की तरफ से अफगानिस्तान को एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन की 500,000 डोज भेजे गए। बता दें इस वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी अभी तक इंतजार है।

स्वास्थ्य मंत्रालय में टीकाकरण कार्यक्रम के प्रमुख गुलाम दस्तगीर नाज़री ने बताया कि काबुल में खुराक तब तक संग्रहित की जाएगी, जब तक कि आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी न मिल जाए। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिलने की संभावना है।

विदेशी जमीन से प्रोपेगैंडा का जवाब देने में जुटे दूतावासों के अधिकारी, प्रभावशाली लोगों से कर रहे संपर्क

नई दिल्ली । किसान आंदोलन पर बाहरी देशों में किए जा रहे कुप्रचार का कूटनीतिक तरीके से जबरदस्त जवाब दिया जा रहा है। विदेशों में मौजूद भारतीय मिशनों के अधिकारी संबंधित देशों में प्रभावशाली लोगों से इस मसले पर सम्पर्क कर रहे हैं। उन्हें भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश के पीछे की साजिश से अवगत कराते हुए अपना पक्ष रखा जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे हैंडल संचालित हो रहे हैं, जिनका स्रोत पाकिस्तान में खालिस्तान समर्थक तत्व हैं। इस संबंध में सैकड़ों अकॉउंट की जानकारी भी एजेंसियों की ओर से साझा की गई है।

सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने अलग-अलग देशों में स्थित भारतीय दूतावासों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह वहां के प्रभावशाली लोगों से संपर्क करके उनकी राय जानें और उनकी राय को साझा करें। साथ ही अपना पक्ष भी प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि इस मुद्दे पर एफएओ, आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे संगठनों के संपर्क में लगातार बने हुए हैं।

बाहरी देशों में इस कार्य में जुटे अधिकारियों को प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए भी कुप्रचार - प्रोपेगैंडा का जवाब देने को कहा गया है। कुछ दिन पहले बाहर से फैलाए जा रहे प्रोपेगैंडा के बाद ट्विटर पर विदेश मंत्रालय के बयान ने पहले 24 घंटों में ही 1.72 करोड़ इंप्रेशन और 14 लाख के करीब इंगेजमेंट पाए थे। सभी दूतावास और कांसुलेट्स हाल ही में उठाए गए मानवाधिकार मुद्दों के बारे में विदेशी सरकारों से संपर्क में रहने के अलावा सोशल मीडिया पर भी चल रहे रुख की परख कर रहे हैं।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाहर से भारत की छवि को बिगाड़ने की कोशिशों के प्रति आगाह किया है।

गुलमा नबी आजाद से रामदास अठावले बोले- राज्यसभा को आपकी जरूरत, कांग्रेस वापस नहीं लाती है तो हम करेंगे

नई दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। इस मौके पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास अठावले ने कहा कि आपको राज्यसभा में वापस आना चाहिए। अगर कांग्रेस आपको नहीं लाती है तो हम आपको वापस लाने के लिए तैयार हैं। इस सदन को आपकी जरूरत है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसभा में बोल रहे थे तो कई ऐसे मौके आए जब वे पुरानी बातों को याद कर भावुक हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर की उस घटना का जिक्र किया, जिसमें आतंकी हमले में गुजरात के कई लोग मारे गए थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद सहित चार सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें शुभकामनाएं दीं और कहा कि सदन के अगले नेता प्रतिपक्ष को आजाद द्वारा स्थापित मानकों को पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजाद ऐसे नेता हैं जो अपने दल के साथ साथ सदन और देश की भी चिंता करते रहे है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के पद पर रहते हुए उन्होंने कभी दबदबा स्थापित करने का प्रयास नहीं किया।

दोनों सदनों में आजाद के लंबे कार्यकाल का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सौम्यता, विनम्रता और देश के लिए कुछ कर गुजरने की कामना प्रशंसनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजाद की यह प्रतिबद्धता उन्हें आगे भी चैन से नहीं बैठने देगी और उनके अनुभवों से देश लाभान्वित होता रहेगा।

प्रधानमंत्री ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे और वह स्वयं गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसी दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में गुजरात के कुछ पर्यटक मारे गए थे। मोदी ने कहा कि आजाद ने जब उन्हें फोन पर इसकी जानकारी दी तो उनके आंसू रूक नहीं रहे थे और ऐसा लगा कि आजाद ने परिवार के सदस्य के रूप में गुजरात के प्रभावित लोगों की चिंता की। प्रधानमंत्री इस घटना का जिक्र करते हुए खुद भावुक हो गए।

प्रधानमंत्री ने आजाद के शौक का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपने सरकारी बंगले में एक सुंदर बगीचा तैयार किया है जो कश्मीर घाटी की याद दिला देता है।

आजाद के साथ ही भाजपा के शमशेर सिंह मन्हास, और पीडीपी के मीर मोहम्मद फ़ैयाज तथा नजीर अहमद लवाय का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। आजाद और नजीर अहमद का कार्यकाल 15 फरवरी को और मन्हास तथा मीर फयाज का कार्यकाल 10 फरवरी को पूरा हो रहा है।

मोदी ने चारों सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे उच सदन की शोभा बढ़ाने वाले, सदन में जीवंतता लाने वाले तथा सदन के माध्यम से जनसेवा में रत रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवकाशग्रहण कर रहे सदस्य अब नए कार्य की तरफ कदम रख रहे हैं।

शशि थरूर और वरिष्ठ पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ट्रैक्टर रैली को लेकर गलत ट्वीट करने के मामले में गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ ही छह अन्य वरिष्ठ पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भ्रामक ट्वीट करने के मामले में इनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले दो हफ्तों के लिए कायम रखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कर्नाटक, हरियाणा रायों को भी नोटिस जारी किया है। इन सभी पर ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत को लेकर गलत जानकारी ट्वीट करने के आरोप में अलग-अलग रायों में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर भी अगली सुनवाई तक रोक बढ़ा दी है। मामले में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी पर लगी रोक का विरोध किया। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हम इन ट्वीट्स की वजह से हुए भयानक प्रभाव को दिखाएंगे। इन ट्विटर हैंडलों के लाखों फॉलोअर्स हैं।

शशि थरूर की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि थरूर इस वक्त दिल्ली में हैं और उनपर गंभीर आरोप हैं, इसलिए अंतरिम सुरक्षा की जरूरत है। सिब्बल ने कहा, जांच एजेंसी कभी भी मुझे गिरफ्तार कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, हम आपकी बात सुनेंगे लेकिन क्या आप उन्हें गिरफ्तार करने जा रहे हैं? इस पर मेहता ने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ हैं। पीठ ने नोटिस जारी करते अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक को बरकरार रखा और दो हफ्ते बाद के लिए सुनवाई टाल दी।

जाह्नवी कपूर के हॉट फोटोशूट ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

बॉलीवुड की एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपनी मां दिवंगत अदाकार श्रीदेवी की तरह ही इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। जाह्नवी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अपनी हॉट और ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस के दिलों पर राज करती है। जाह्नवी कपूर का फैशन सेंस फैंस को बेहद पसंद आता है। वहीं जाह्नवी भी अपनी अपने दिलकश अदाएं दिखाने से जरा भी पीछे नहीं रहती। हाल ही में जाह्नवी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी बेहद हॉट और स्टाइलिश तस्वीरें शेयर की है। एक्ट्रेस का यह लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों में जाह्नवी सिल्वर कलर के हॉट ड्रेस में ग्लैमरस अंदाज में एक से बढ़कर एक पोज देती नजर आ रही है। जाह्नवी की इस कातिलाना अदाओं से फैंस घायल हो गए है। जाह्नवी ने इन तस्वीरों को शेयर कर कैप्शन में लिखा, 'क्या यह अजीब है कि हमने ऐसा एक दिन के मज़े के लिए किया।' जाह्नवी की यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उनके कई सारे फैंस कमेंट्स कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है। वर्क फ्रंट कि बात करें तो जाह्नवी ने हाल ही में 'गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल' में नजर आई थीं। जाह्नवी ने 2018 में फिल्म धड़क से बॉलीवुड में कदम रखा था। जिसके बाद वे नेटफ्लिक्स कि वेब सीरीज 'घोस्ट स्टोरीज' का हिस्सा थीं। जाह्नवी कपूर की अपकमिंग फिल्मों में करण जौहर की पीरियड ड्रामा तख्त, हॉरर कॉमेडी रूही अफज़ा और कार्तिक आर्यन के साथ दोस्ताना 2 शामिल हैं। इतना ही नहीं एक्ट्रेस ने हाल ही में फिल्म 'गुड लक जेरी' भी साइन की है।

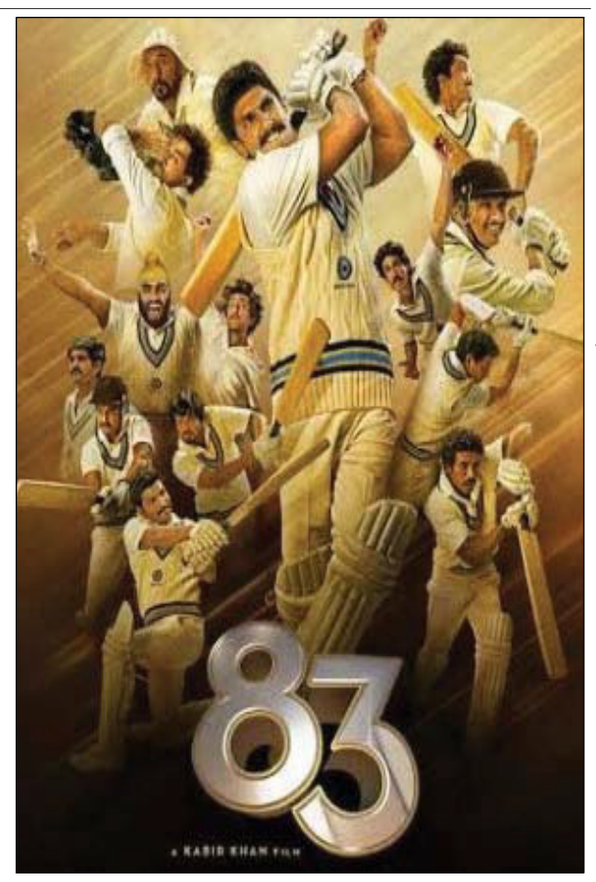

रणवीर सिंह की '83' जून में हो सकती है रिलीज

कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा और इस वजह से दो बड़ी फिल्मों की रिलीज अटक गई। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी और रणवीर सिंह की 83 की रिलीज लगभग एक साल से रूकी हुई है। इन फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वालों ने शानदार ऑफर्स भी दिए, लेकिन इस फिल्म के निर्माताओं ने इंतजार करना उचित समझा और वे चाहते हैं कि फिल्म पहले थिएटर्स में रिलीज हो। खबर है कि फिल्म रोकने के कारण दोनों फिल्मों का ब्याज 25 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है। दोनों फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट रिलीज करने वाला है। खबर है कि पहले अक्षय कुमार की सूर्यवंशी रिलीज होगी। इसे 2 अप्रैल को रिलीज किया जाएगी, जिसकी ऑफिशियल घोषणा बस होने ही वाली है। रोहित शेट्टी निर्देशित इस फिल्म में कैटरीना कैफ भी हैं। साथ ही सिंघम के रूप में अजय देवगन और सिम्बा के रूप में अजय देवगन इस मूवी में नजर आएंगे। रिलायंस एंटरटेनमेंट अपनी दूसरी मूवी 83 को जून में रिलीज करने का प्लान बना रहा है। यह फिल्म 1983 में विश्वकप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम पर आधारित है। 25 जून 1983 को भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्वकप जीता था। बताया जा रहा है कि 25 जून 2021 को फिल्म को रिलीज किया जा सकता है। हालांकि फिल्म से जुड़े सूत्र का कहना है कि यह फिल्म जून में कभी भी रिलीज की जा सकती है। इस फिल्म में रणवीर सिंह ने भूतपूर्व कप्तान कपिल देव का रोल अदा किया है। कबीर खान निर्देशित इस मूवी में रणवीर के अलावा दीपिका पादुकोण, साकिब सलीम, एमी विर्क, ताहिर राज भसीन जैसे कई कलाकार नजर आएंगे।

'लाल सिंह चड्ढा' के पोस्ट प्रॉडशन में दिन-रात लगे हुए हैं आमिर खान

पिछले काफी समय से आमिर खान की आने वाली फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' लगातार चर्चा में बनी हुई है। अब इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है और पोस्ट प्रॉडक्शन का काम चल रहा है। आमिर खान भी पूरी तरह से इस फिल्म के पोस्ट प्रॉडक्शन में डायरेक्टर अद्वैत चंदन के साथ लगे हुए हैं। इस फिल्म के पोस्ट प्रॉडक्शन पर तेजी से काम किया जा रहा है ताकि इसे इस साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज किया जा सके। आमिर खान के एक नजदीकी सूत्र ने बताया है कि आमिर खान और फिल्म के डायरेक्टर अद्वैत चंदन रोजाना 'लाल सिंह चड्ढा' की एडिटिंग पर काम कर रहे हैं ताकि यह तय समय पर रिलीज हो सके। पता चला है कि आमिर खान ने काम में कोई डिस्टर्ब न करें इसलिए अपना फोन भी ऑफ कर दिया है। यह फिल्म काफी समय से बन रही है और इसमें आमिर खान के किरदार का जिंदगी का कई सालों का सफर एक साथ दिखाया जाएगा। यह फिल्म 1994 में आई टॉम हैंस की ऑस्कर विनिंग फिल्म 'फॉरेस्ट गप' का हिंदी अडैप्टेशन है। फिल्म में आमिर खान के साथ करीना कपूर खान लीड रोल में दिखाई देने वाली हैं। फिल्म में विजय सेतुपति और मोना सिंह भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे।

शमा सिकंदर ने फैंस को धन्यवाद दिया

अभिनेत्री शामा सिकंदर ने हाल ही में पुरानी यादों में खो गईं, जहां उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक लाइक वाले फोटो के लिए फैंस का आभार व्यक्त किया। अभिनेता ने फैंस का आभार व्यक्त करते हुए कहा, 'मेरे फैंस का बहुत-बहुत आभार, वे मेरे प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं। मैं खुद का बेस्ट वर्जन हूं और अपने फैंस के लिए बेटर वर्जन। उनका जबरदस्त प्यार मुझे आगे बढ़ाता है और मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। ये मेरी लाइफ, सेवन और बाल वीर जैसे शो में अपनी टेलीविजन यात्रा के लिए जानी जाने वाली शमा कहती हैं, ''मैं बहुत छोटी थी तब से प्रशंसकों का प्यार लगातार बना रहा। फैंस मेरे लिए बहुत कीमती है।''

सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म हंसी तो फंसी के 7 साल पूरे, एक्टर ने शेयर किया इमोशनल नोट

बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सोलो फिल्म हसी तो फसी ने 8 फरवरी को रिलीज के सात साल पूरे कर लिए हैं। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा इस मौके पर फिल्म से जुड़ी अपनी यादों को लेकर एक भावनात्मक नोट सोशल मीडिया पर साझा किया है। उन्होंने नोट में परिणीति चोपड़ा का भी जिक्र किया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म के बारे में बात करते हुए लिखा कि फिल्म हंसी तो फंसी मेरी दूसरी फिल्म थी लेकिन सोलो के नजर से यह मेरी पहली फिल्म थी। ये मेरी एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए मुझे आज भी तारीफें मिलती हैं। अब तक कि सभी फिल्मों से सबसे प्यार और पसंदीदा किरदार मैंने इस फिल्म में ही निभाया था। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मैंने काफी कॉमेडी भी की। उन्होंने आगे लिखा, 'पहचाने जाने की विशिष्ट भावना बहुत ताज़ा और नई थी और मुझे एहसास हुआ कि मैं एक हिंदी फिल्म हीरो होने के अपने सपने को जी रहा था! आज मैं इस दिन को याद करते हुए धन्य महसूस करता हूं, पूरी टीम और मेरे सह को धन्यवाद।

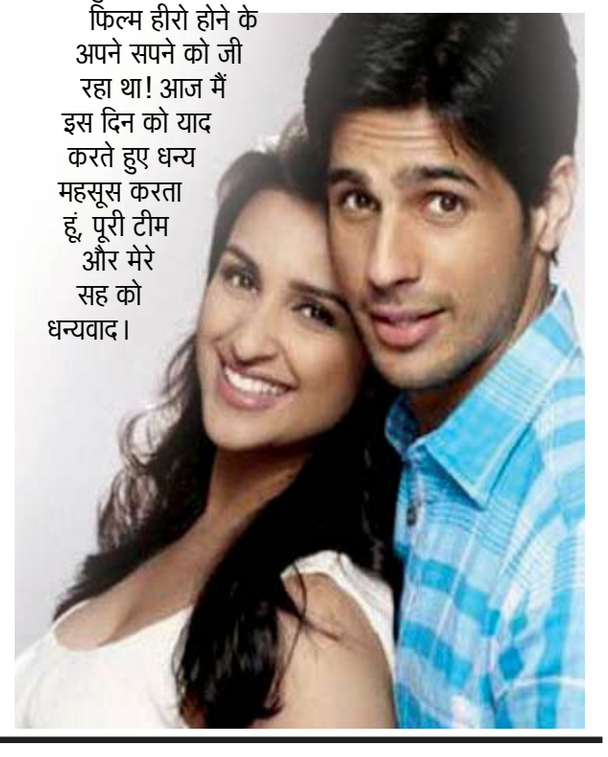

सलमान खान से मुकाबले में जॉन अब्राहम पीछे हटने को तैयार नहीं

ईद पर होकर रहेगी टक्कर

हर वर्ष ईद पर सलमान खान अपनी फिल्म लेकर आते ही हैं, यह एक अघोषित परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। वैसे तो राधे को पिछली ईद पर रिलीज होना था, लेकिन कोराना वायरस के कारण इस प्लान पर पानी फिर गया। अब इस ईद पर सलमान खान अपनी यह मूवी रिलीज कर रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म वालों ने सलमान को 'राधे' के लिए कई लुभावने ऑफर्स दिए, लेकिन सलमान टस से मस नहीं हुए। उन्होंने सिनेमाघर वालों की उस अपील का ध्यान रखा जिसमें कहा गया था कि वे राधे को पहले सिनेमाघर में ही रिलीज करे ताकि इन सिनेमाघरों को घाटे से उबरने में कुछ मदद मिल सके। इसी बीच कुछ दिन पहले जॉन अब्राहम को लेकर बनाई जा रही 'सत्यमेव जयते 2' के निर्माता-निर्देशक ने भी ऐलान कर दिया कि वे भी अपनी फिल्म को ईद पर रिलीज करेंगे। देखते, समझते-बूझते उन्होंने सलमान की फिल्म से टक्कर लेने की ठानी। इस बात पर कुछ लोगों ने यह सोच कर विश्वास नहीं किया कि यह पब्लिसिटी स्टंट है। इस टक्कर के बहाने जॉन की फिल्म को थोड़ा प्रचार मिल जाएगा और ऐन मौके पर वे अपनी फिल्म की रिलीज डेट को आगे-पीछे कर देंगे। ऐसा बॉलीवुड में कई निर्माता करते भी आए हैं। लेकिन यह टक्कर तो होकर ही रहेगी। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि जॉन अपनी फिल्म की रिलीज को आगे-पीछे नहीं करने वाले। वे ईद पर ही अपनी फिल्म रिलीज करेंगे, भले ही उस दिन सलमान की राधे रिलीज हो रही है। सभी जानते हैं कि जॉन और सलमान में अच्छे संबंध नहीं है। किसी बात पर जॉन से सलमान नाराज है और उनकी नाराजगी आसानी से दूर नहीं होती है। जॉन भी सलमान से नाखुश हैं इसलिए जानते-बूझते वे सलमान की फिल्म के आगे अपनी मूवी रिलीज कर रहे हैं। यदि और कोई फिल्म होती तो संभव था जॉन इस टक्कर की हिम्मत नहीं करते, लेकिन सत्यमेव जयते 2 की कामयाबी का उन्हें भरोसा है। इस सीरिज की पहली फिल्म हिट रही थी, खासतौर पर छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में फिल्म ने शानदार सफलता हासिल की थी। सत्यमेव जयते 2 भी मसाला फिल्म है और इसी तरह के दर्शक वर्ग को ध्यान में रख कर बनाई गई है। जॉन को उम्मीद है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग लेगी, भले ही सलमान की राधे रिलीज हो रही है। जहां तक बिजनेस का सवाल है तो दोनों ही फिल्म को इस टक्कर का नुकसान उठाना पड़ेगा। निश्चित रूप से राधे बड़ी फिल्म है, लेकिन सत्यमेव जयते 2 थोड़ा बिजनेस तो प्रभावित करेगी ही। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब एक फिल्म की रिपोर्ट खराब निकलती है। दर्शक फौरन उस फिल्म को देखने का इरादा त्याग देते हैं और दूसरी फिल्म देखने का मन बना लेते हैं। बहरहाल, ईद दूर है। हो सकता है कि कुछ फेरबदल हो जाए, लेकिन अभी के जो हालात हैं उसे देख कहा जा सकता है कि यह टक्कर तो होकर ही रहेगी।

बाजार समीक्षा

मध्य प्रदेश में कपास फसल बढ़कर 20 लाख गांठ अनुमानित

कपास उत्पादन अनुमान में बढ़ोत्तरी

इंदौर। पहली अक्टूबर से शुरू चालू कपास फसल सीजन में कॉटन उद्योग ने दूसरी बार उत्पादन अनुमान में बढ़ोतरी की है। कॉटन एसोसिएशन आफइंडिया (एसईए) के अनुसार चालू सीजन में कपास 360 लाख गांठ (प्रति गांठ.170 किलो) उत्पादन का अनुमान है, जो इससे पूर्वानुमान से 1.50 लाख गांठ ज्यादा है।

एसईए ने आरंभिक अनुमान में 356 लाख गांठ उत्पादन अनुमान जारी किया था, जिसे जनवरी में अनुमान को बढ़ाकर 358.50 लाख गांठ किया गया था। एसईए द्वारा जारी तीसरे आरंभिक अनुमान के अनुसार 360 लाख गांठ उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले साल के बराबर है। उद्योग के अनुसार चालू सीजन में उत्तर भारत के राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास उत्पादन गत वर्ष के 63 लाख से घटकर 62 लाख गांठ का अनुमान है। मध्य भारत के गुजरात में 94 लाख व महाराष्ट्र

में 85 लाख गांठ का अनुमान जताया है जबकि पिछले साल गुजरात में 95 लाख और महाराष्ट्र में 87 लाख गांठ उत्पादन हुआ था। मध्य प्रदेश में उत्पादन अनुमान 20 लाख गांठ की उम्मीद है, जोकि पिछले साल के 18 लाख गांठ थी। दक्षिण भारत के राज्यों तेलंगाना 40.50 लाख व आंध्रप्रदेश में 16 लाख गांठ का अनुमान है। पिछले साल तेलंगाना में 52 लाख व आंध्र में 15.25 लाख गांठ हुआ था। कर्नाटक में 20 लाख से बढ़कर 24.50 लाख व तमिलनाडु में गत वर्ष के बराबर 5 लाख गांठ अनुमानित है।

चालू सीजन में कॉटन आयात घटेगा, निर्यात बढ़ेगा

इंदौर। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के अनुसार चालू सीजन में कॉटन आयात गत वर्ष के 15.50 लाख से घटकर 14 लाख गांठ होने का अनुमान है। सीजन के पहले चार महीनों में जनवरी तक करीब 6 लाख गांठ कॉटन का आयात हो चुका है। वहीं चालू सीजन में कॉटन निर्यात 54 लाख गांठ होने का अनुमान है, जोकि पिछले साल के 50 लाख गांठ की तुलना में ज्यादा है। एसईए के अनुसार 31 जनवरी 2021 तक भारत से करीब 29 लाख गांठ की शिपमेंट हो चुकी है। उद्योग के अनुसार 31 जनवरी 2021 तक देशभर के राज्यों की मंडियों में 255.25 लाख गांठ की आवक हो चुकी है।

सोया तेल एवं सोयाबीन में तेजी का क्रम जारी

इंदौर। मलेशिया एवं शिकागो वायदा कारोबार में तेजी के बीच घरेलू बाजार में भी मंगलवार को सोया रिफाइंड एवं सोयाबीन की कीमतों में तेजी का क्रम जारी था। मलेशिया पाम तेल वायदा 1025 डॉलर प्रतिटन था। केएलसीई 133 रिंगिट ऊंची बंद हुई। शिकागो सोया तेल वायदा रनिंग में 62 सेंट ऊंचा चल रहा था। गत रात्रि को 97 सेंट बढ़कर बंद हुआ था। स्थानीय बाजार में खाद्य तेल प्रति 10 किलो सोया रिफाइंड 1120-1125, साल्वेंट 1060-1065, मुंबई 1135, मूंगफली तेल 1450-1470, मुंबई 1460, गुजरात 1425, पाम तेल मुंबई 1105, इंदौर 1150, कपास्या तेल इंदौर 1085, महाराष्ट्र 1085, गुजरात 1100 रु बोला गया। **सोया तेल प्लांट डिलीवरी-**प्रति 10 किलो अवि 1130, विप्पी 1127, प्रकाश 1125, धानुका 1120, केशव 1130, एमएस नीमच 1130 रु था। **सोयाबीन प्लांट सौदो में-** प्रेस्टिज 4825, प्रकाश 4825, मालू 4825, खंडवा 4800, कृति 4825, रामा 4600, सिमरन 4825 रुपए क्विंटल थे। **कपास्या खली और बढ़ी-** मंगलवार को भी तेजी जारी थी। दाम प्रति 60 किलो इंदौर , देवास उज्जैन 1700-1705, खंडवा-बुरहानपुर 1675-1680 रु एवं अकोला 2375 रु क्विंटल के भाव थी।

सोना-चांदी में बढ़त कायम

इंदौर। ग्लोबल बुलियन मार्केट में तेजी के चलते भारतीय सराफा बाजारों में मंगलवार को भी सोना-चांदी में बढ़त कायम थी। कॉमेक्स एक्सचेंज में रनिंग सौदों के तहत सोना ऊंचे में 1849, नीचे में 1837.70 डॉलर एवं चांदी ऊंचे में 2786, नीचे में 2734 सेंट प्रतिऔंस के दायरे में मजबूत थी। इंदौर सराफा में 7.10 बजे गत दिवस की तुलना में सोना 250 रु बढ़कर 49625 रु प्रति 10 ग्राम एवं चांदी 350 रु बढकर 68750 रु किलो बताई जा रही थी। दिन के कारोबार के दौरान सोना ऊंचे में 49700, नीचे में 49520 एवं चांदी ऊंचे में 69100 नीचे में 68650 रु के दायरे में थी। चांदी सिक्का 750 रु प्रति नग पर स्थिर बताया गया। **रतलाम सराफा**-आरटीजीएस सौदो में सोना 49800 रि प्रति 10 ग्राम एवं चांदी 69100 रु प्रति किलो थी। चांदी सिक्का 775 रु नग बताया गया। । **उज्जैन सराफा-**सोना 49800 रु प्रति 10 ग्राम व चांदी 69200 रु किलो टैक्स अलग के भाव थी। चांदी सिक्का 800 रुपए नग था।

मसूर व उड़द में मजबूती का रुख

इंदौर। दाल मिलों की खरीदी के चलते मसूर एवं उडद की कीमतों में तेजी का रुख था। दालों में कमजोर मांग के बीच दाम स्थिर थे। डॉलर चना जूना 2000, नया 100 बोरी आवक हुआ।

मंडी में चनाकांटा 4700-4750, डॉलर चना नया 5500-6200, जूना 5400-6500, निर्यात सौदो में 42-44 काउंट 7000-44-46 काउंट 6800, 58-60 काउंट 6000 मसूर 5300, मूंग 8000-8300, एवरेज 7000-7800, उडद 8000-8200, बेस्ट 8500, एवरेज 6500-7500, तुवर लोकल 6500-6800, महाराष्ट्र सफेद 6900-7000 लाल 7200, कर्नाटक 7300-7400 रु थी।

दाल चावल के भाव

दालें प्रतिकिलो- चना दाल 55.5-60.5, तुवर दाल जूनी 94-101, नई 102-105, मसूर दाल 62.5-65.5, मूंग दाल 86-89, मोगर 93-97 उडद दाल 86-90 मोगर 103-111 रु। **चावल:** दयाल दास अजित कुमार बासमती (921) 9000-9500, तिबार 7500-8000, दुबार 6500-7000, मिनी दुबार 6000-6500 मोगरा 3500-5500, बासमती सैला 6500-8500, कालीमूंछ डिनर किंग 7000, राजभोग 6000, दूबराज 3500-4000, परमल 2500-2600 सैला हंसा 2450-2550 रु ।

निजी केंद्रों पर भी होगी गेहूं खरीदी!

इंदौर। किसान आंदोलन के पीछे मप्र सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। इसके तहत किसान निजी केंद्रों पर भी गेहूं बेच सकेंगे। इसके लिए निजी क्षेत्र को भी क्रय केंद्र खोलने की अनुमति दी जाएगी।

आईटीसी कंपनी सहित कुछ व्यापारी क्रय केंद्र खोलने की तैयारी में है। दरअसल, अब तक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम व राज्य विपणन सहकारी संघ द्वारा ही गेहूं की एमएसपी पर खरीदी होती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के स्थगन की वजह से मंडी अधिनियम पुराने स्वरूप में आ गया है। इसके बाद प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र को भी केंद्र खोलने की अनुमति देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत व्यापारियों को यदि किसानों से सीधे खरीदना है, तो इन्हें क्रय केंद्र खोलने का लाइसेंस लेना होगा। अभी प्रदेश में फसलों के पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है। स्थानीय मंडी में गेहूं की आवक नया 1000, जूना 4000 बोरी की हुई। भाव पूर्ववत् थे। मिल डिलीवरी इंदौर, देवास, पीथमपुर 1800-1840 जलगांव-अमलनेर धुलिया 1880, पुणे 2040, नगर 2020, हैदराबाद 2050, बैंगलुरु 2120 रुपए क्विंटल रहे।

टूकॉलर की यूजर्स संख्या बढ़ी

नई दिल्ली। ब्रांड समाधान प्लेटफॉर्म टूकॉलर ने स्थानीय सेगमेंट में ढेरों ब्रांड्स को तीव्रवृद्धि करने में समर्थ बनाया है। यह भारत में औद्योगिक स्तरों की तुलना में काफी ज्यादा इंगेजमेंट प्रदान कर रहा है। टियर 2 और 3 शहरों में टूकॉलर की मजबूत उपस्थिति एवं स्थानीय ग्राहकों के साथ कनेक्ट होने की क्षमता के चलते अनेक ब्रांड अपने ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाने एवं भारत में लाखों ग्राहकों के साथ संलग्न होने में समर्थ बने हैं। टूकॉलर का प्रोग्रामेटिक प्लेटफॉर्म ब्रांड्स को विज्ञापन का अभिनव माध्यम प्रदान करता है, जो स्थानीय बाजार में 145 मिलियन से ज्यादा मासिक सक्रिय ग्राहकों को उपयोगी संदेश पहुंचाता है। सागर मानिकपुरी, वाईस प्रेसिडेंट ग्लोबल एड्स बिजनेस, टूकॉलर ने कहा, हमें यह देखकर बहुत खुशी है कि हमारे ब्रांड साझेदार टूकॉलर के 150 मिलियन दैनिक औसत यूजर्स एवं 2 बिलियन दैनिक इंप्रेशंस के अतुलनीय स्केल का उपयोगकर ग्राहकों के साथ सबसे सुगमता से संपर्क स्थापित करनेवाली भाषा के माध्यम से संदर्भात्मक संलग्नता सुनिश्चित कर रहे हैं।

अंचल की मंडी

नीमचः सोयाबीन, रायडा, चना, धनिया, मैथी एवं प्याज के भाव में तेजी का रुख

नीमच, (शंकर बंसल)- मंगलवार को मंडी में सोयाबीन, रायडा, चना, धनिया, मैथी व प्याज की कीमतों में तेजी का रुख था। भाव-गेहूं 1610-1930, जौ 1250-1390, मक्का 1190-1240, सोयाबीन 4450-4700, रायडा 4300-5665, अलसी 5000-5350, मूंगफली 4000-5500, तारामीरा 4200-4321, चना 3800-4580, डॉलर चना 3800-6100, मसूर 4252-4861, उडद 4600-7350, पोस्ता 93000-126000, टिनोपाल पोस्ता 131000, मैथी 4000-5800, धनिया 4000-5900, अजवाइन 9000-14400, इसबगोल 10000-11500, कलौंजी 16000-18660, तिल्ली 5000-8200, असगंध 15000-39200, लहसुन 2100-9700, प्याज 1800-3600 रु। **मंदसौर-**मक्का 1210-1410, उडद 6000-6951, सोयाबीन 3660-4850, गेहूं 1608-1761, चना 3850-4510, मसूर 4260-5221, धनिया 3700-5300, लहसुन 2000-8601, मैथी 4000-5239, अलसी 4800-5464, सरसों 4700-5585, तारामीरा 4150-4321, इसबगोल 8700-11450, प्याज 1210-3200, डॉलर चना 3801-6200, तिल्ली 7500-7800, मटर 2100-3800, असालिया 3681-4389 रु। **धार-**मंडी में 7197 बोरी आवक के बीच सोयाबीन 2680-5100, गेहूं 1575-2021, डॉलर चना 3490-6455, देशी चना 3595-4715, बटला 1500-4472, मक्का 1162 -1246, मसूर 4845-4985 रु। **नीमरानी-**गेहूं 1040 क्विंटल आवक हुआ, जो 1665-1755 रु बिका। **अंजड़-** कपास 15 वाहन, 5 बैलगाड़ी आया, जो 3050-5830 बिका। **खंडवा-** कपास 61 वाहन आवक के बीच भाव-कपास 4700-6183, सोयाबीन 3700-5800, गेहूं 1525-1844, तुवर 5301-6940, मक्का 1050-1248, चना 3500-4621, उडद 3200-4600 रु थे। **खेतिया**-कपास 190 वाहन, 05 बैलगाड़ी आवक हुआ, जो 4700-6150 रु बिका। **खरगोन-** कपास 240 वाहन, 40 बैलगाड़ी आवक हुआ। भाव-कपास 4600-6610, गेहूं 1650-1805, चना 3001-4640, ज्वार 1100-1150, मक्का 1270-1300, तुवर 6840-6500, सोयाबीन 4773-4570 रुपए क्विंटल के थे। **महू-** मंडी में सोयाबीन 3771-4852, चना 4001-4450, बिटकी 3981-4540, डॉलर चना 4061-5471, गेहूं 1626-1814, मक्का 1156 रु। **धामनोद-** कपास 72 वाहन, 15 बैलगाड़ी, मक्का 31, सोयाबीन 4, डॉलर चना 1, मौसमी चना 2, गेहूं 19 वाहन आवक हुआ। भाव-कपास 4630-6200, मक्का 1100-1275, सोयाबीन 4475-4625, गेहूं 1660-1738, डॉलर चना 5905, मौसमी चना 4395-4505 रु। **बड़नगर**-मंडी में 7632 बोरी आवक हुई। भाव-गेहूं 1540-1830, चना 4080-4760, डॉलर चना 4400-6300, मसूर 4000-4820 रुपए।

बादाम सेहत के लिए फायदेमंद

नई दिल्ली। इस वैलेंटाइन डे पर आप अपने प्रियजनों को सेहत के लिए फायदेमंद बादाम तोहफे के रूप में दे सकते हैं। बादाम विटामिन ई, मैग्नीशियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, जिंक जैसे 15 पोषक तत्वों का स्रोत है। दिल की सेहत, त्वचा की सेहत और वजन को नियंत्रित रखने में फायदा देने वाले ये बादाम ब्लेड शुगर को भी नियंत्रित करने में मदद करते हैं। प्रमुख बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान कहती हैं, वैलेंटाइन डे पर मैंने तोहफे में बादाम देने की सोची है, क्योंकि यह अच्छी सेहत का उपहार माना जाता है। इसमें विटामिन बी2, विटामिन ई, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं जोकि एक सेहतमंद जिंदगी जीने में मदद करते हैं। इसके अलावा बादाम में इम्युनिटी को बेहतर बनाने वाले पोषक तत्व जिंक, फॉलेट आयरन होते हैं जोकि इसे देने के लिए एक परफेक्ट तोहफा बनाता है। इस तोहफे को पाने वाले की संपूर्ण सेहत बेहतर होती है।

एमजी मोटर की नई जेडएस ईवी लॉन्च

नई दिल्ली। एमजी मोटर इंडिया ने नया जेडएस ईवी 2021 लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 20.99 लाख रुपए नई दिल्ली है। अपडेटेड वर्जन बेस्ट इन क्लास 44.5 किलो वॉट हाईटेक बैटरी के साथ आता है और इसमें 419 किमी की सर्टिफाइड रेंज है। नए 215-55-आर17 टायर से लैस इस वाहन में बैटरी पैक ग्राउंड क्लीयरेंस क्रमशः 177 मिमी और 205 मिमी तक बढ़ाए गए हैं। अपने भागीदारों के साथ देशभर में चार्जिंग इकोसिस्टम का विस्तार करने के बाद जेडएस ईवी 2021 को अब 31 शहरों में बुकिंग के लिए उपलब्ध कराया गया है। कार को जनवरी 2020 में पांच शहरों में लॉन्च किया गया था और उसके बाद धीरे-धीरे शहर जोड़ते चले गए। एमजी मोटर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजीव चाबा ने कहा, एमजी जेडएस ईवी 143 पीएस पावर और 350 एनएम टॉर्क के साथ आती है और यह 8.5 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती है। यह दो वैरिएंट्स में एक्साइट और एक्सक्लूसिव में उपलब्ध है।

नेटकॉन 2021 मीट का आयोजन

नई दिल्ली। जैविक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने पहले पावर मीट नेटकॉन 2021 का सफल आयोजन किया। जैविक इंटरनेशनल कंपनी द्वारा आयोजित नेटकॉन 2021 में हिस्सा लेने के लिए अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, दाहोद, उदयपुर, इंदौर जैसे शहरों और देशभर से 150 से अधिक सम्मानित डीलर्स ने भाग लिया। नेटकॉन 2021 में आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया के सिद्धांतो के तहत एलईडी टीवी, नियमित टीवी, पंखो एवं स्पीकर्स की एक विस्तृत श्रृंखला की प्रदर्शनी लगाई गई। इसके आलावा इम्पोर्टेड एयर कूलर्स की रेंज को भी दर्शाया गया। जैविक इंटरनेशनल के सह संस्थापक अमित नेनवानी और दीपक जियानी ने बताया की जैविक इंटरनेशनल की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी और जो कुछ ही वर्षो में गुजरात राज्य के सबसे तेजी से बढ़ते कंस्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों में से एक टॉप कंपनी की तरह मजबूत रूप से उभरी है।

मप्र से 79300 टन मसूर की खरीद को मंजूरी

इंदौर। केंद्र ने मध्यप्रदेश से चालू रबी सीजन 2020-21 में 79300 टन मसूर की सरकारी खरीद को मंजूरी दी है। कृषि मंत्रालय के अनुसार मसूर की एमएसपी पर खरीद नेफेड व राज्य सरकार की एजेंसियां करेगी। किसानों को राज्य सरकार की एजेंसियों के पास पंजीकरण कराना होगा। वहीं केंद्र ने आंध्रप्रदेश से चालू रबी सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 139900 टन चना, 81650 टन उड़द और 19950 टन मूंग की खरीद को मंजूरी दे दी है।

वैश्विक सराफा

विवरण	सोना	चांदी
ऊंचे में	1849.00	27.86
नीचे में	1837.70	27.34
रनिंग में	1844.00	27.61

जायफल, जावित्री व हल्दी में सुधार

इंदौर। किराना बाजार में मंगलवार को जायफल एवं जावित्री की कीमतों में 20-25 रु किलो का सुधार दर्ज हुआ। हल्दी में भी तेजी का क्रम जारी था। शकर के दाम मामूली बढ़त लिए नजर आए। नारियल की आवक 4 गाड़ी हुई। जीरे में मामूली तेजी का रुख था।

थोक किराना बाजार में शकर 3320-3350, सुपर 3360-3370, एम-3390-3425, गुड़ भेली 2900, कटोरा 3150, लड्डू 3150-3250, कालीमिर्च कालामोती 350, दीपक 364, गणेश 397, मटरदाना 418, जीरा पंजा 153, खुशबू 155, हल्का जीरा 140-150, हल्दी सांगली 145, निजामाबाद 100-115, पीसी हल्दी प्रति 15 किलो 1550-1800, नारियल प्रति बोरी 120 भर्ती 1600-1650, 160 भर्ती 1751-1800, 200 भर्ती 1951-2000, 250 भर्ती 2100-2150, खोपरा गोला 175-190, खोपराबूरा प्रति 15 किलो 2900-4300, साबूदाना 4200-5200, वरलक्ष्मी 5500, सौंफ मोटी 120-185, हल्की 70-100, लौंग 425-450, दालचीनी 260-270, जायफल 700-750, जावत्री 2000-2100, बड़ी इलायची 560-750, बाद्यान्न फूल 785-850, तरबूज मगज 120-125, सौंठ 250-300, चारौली 1230-1400, इलायची एक्स्ट्रा बोल्ड 2000-2200, बोल्ड 1950-1975, मध्यम बोल्ड 1850-1875, मिनी बोल्ड 1800-1825, पानपट्टी 1700-1750, खसखस 1150-1250, मध्यम 670-900, हल्की 425-575, काजू (240) 880, (320) 740, डब्ल्यू वन 715, एस डब्ल्यू 700 रुपए ।

भारतीय शेर अंग्रेजों के आगे ढेर

इंग्लैंड ने 227 रन से हराया, सीरीज में 1-0 की बढ़त, टेस्ट चैंपियनशिप की राह मुश्किल

चेन्नई (एजेंसी)। लेफ्ट आर्म स्पिनर जैक लीच (76 रन पर चार विकेट) और तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (17 रन पर तीन विकेट) की घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड ने भारत को पहले क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन मंगलवार को 227 रन के बड़े अंतर से हराकर चार मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस हार से भारत की आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने की राह मुश्किल हो गई है। इंग्लैंड ने भारत के सामने 420 रन का बेहद मुश्किल लक्ष्य रखा था और उसने मेजबान टीम की पारी अंतिम दिन दूसरे सत्र में 192 रन पर समेट दी। इंग्लैंड ने इस तरह विदेशी जमीन पर अपनी लगातार छठी जीत दर्ज की। इंग्लैंड ने अपने कप्तान जो रुट को उनके 100वें टेस्ट में जीत का शानदार तोहफा दे दिया। रुट ने इस मुकाबले में पहली पारी में 218 रन की रिकॉर्डतोड़ पारी खेली और इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच बने। इस हार से भारत की आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने की राह मुश्किल हो गई है। भारत को फाइनल में जगह बनाने के लिए यह सीरीज 2-1 या 3-1 के अंतर से जीतनी है जबकि इंग्लैंड को 3-1, 3-0 या 4-0 से जीत हासिल करनी है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने संघर्षपूर्ण 72 और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने 50 रन बनाए लेकिन वे टीम को हार से नहीं बचा सके। भारत के अन्य बल्लेबाज असमान उछाल और टर्न लेती पिच पर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए। इंग्लैंड की तरफ से लीच ने चार, एंडरसन ने तीन और जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स तथा डोमिनिक बेस ने एक-एक विकेट लिया। भारत ने सुबह एक विकेट पर 39 रन से आगे खेलना शुरू किया था। लेकिन अगले दो सत्रों के अंदर भारतीय पारी सिमट गई। गिल 50, चेतेश्वर पुजारा 15, विराट 72, उपकप्तान अजिंक्या रहाणे शून्य, ऋषभ पंत 11, वाशिंगटन सुन्दर शून्य और रविचंद्रन अश्विन नौ रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा कल 12 रन बनाकर आउट हुए थे।

रूट ने की वान की बराबरी, संयुक्त रूप से बने इंग्लैंड के सबसे सफल कप्तान

जो रूट इंग्लैंड के संयुक्त रूप से सबसे सफल कप्तान बन गए हैं और उन्होंने माइकल वान की बराबरी कर ली है। रूट की कप्तानी में इंग्लैंड ने भारत को पहले टेस्ट में मंगलवार को 227 रन से हराया और चार टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। रूट की अपनी कप्तानी में 47 टेस्टों में यह 26वीं जीत थी और इसके साथ ही उन्होंने माइकल वान की बराबरी कर ली है जिन्होंने अपनी कप्तानी में 51 टेस्टों में 26 मैच जीते थे। रूट ने एशिया में छह टेस्टों में कप्तानी की है और सभी छह टेस्ट जीते हैं। उन्होंने श्रीलंका में लगातार पांच मैच जीते हैं।

इंग्लैंड (2018-21) ने एशिया में लगातार छह टेस्ट जीते

रूट ने 2018 में श्रीलंका को 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद 2021 में श्रीलंका को 2-0 से क्लीन स्वीप किया। इंग्लैंड (2018-21) ने एशिया में लगातार छह टेस्ट जीत लिए हैं और वह अब एशिया में लगातार सात टेस्ट जीतने के ऑस्ट्रेलिया (2002-04) के रिकॉर्ड की बराबरी करने से एक जीत दूर रह गया है। एशिया में किसी विदेशी कप्तान के सर्वाधिक मैच जीतने के मामले में रूट से आगे वेस्टइंडीज के क्लाइव लॉयड (17 टेस्ट में सात जीत) और दक्षिण अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ (21 टेस्ट में आठ जीत) हैं।

हार के लिए कोई बहाना नहीं, अगले मैचों में देंगे कड़ी टक्कर: विराट

इंग्लैंड से पहले क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन मंगलवार को 227 रन के बड़े अंतर से हारने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि वह हार के लिए कोई बहाना नहीं देंगे लेकिन अगले तीन मैचों में कड़ी टक्कर देंगे और स्थिति को अपने नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे। मैच के बाद विराट ने कहा, कोई बहाना नहीं। हम अपनी विफलताओं और गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। एक चीज निश्चित है कि अगले तीन मैचों में हम कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं और चीजों को अपने हाथ जाने नहीं देंगे। हमें अच्छी बॉडी लैंग्वेज से खेल की शुरुआत करनी होगी और विपक्षी टीम पर दबाव बनाना होगा। मैदान, पिच की स्थिति और गेंदबाजों के प्रदर्शन को समझना होगा। ये सभी चीजें महत्वपूर्ण होंगी। उन्होंने कहा, हम वापसी की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि किस तरह से शानदार वापसी की जाती है और अगले मैचों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देंगे।

चेन्नई टेस्ट में हार से भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में चौथे स्थान पर खिसका

इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नै में पहले टेस्ट में 227 रन की हार के साथ भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल में चौथे स्थान पर खिसक गया है। चेपॉक में मिली इस जीत से मेहमान टीम ने पहली बार हो रही इस चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने की अपनी संभावनाओं को मजबूत किया। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इसी साल होने वाले फाइनल के लिए न्यूजीलैंड की टीम पहले ही क्वॉलिफाइ कर चुकी है। उसका विजयी अंकों का प्रतिशत 70.0 है और उसे अब कोई सीरीज नहीं खेलनी है। दक्षिण अफ्रीका को घरेलू सीरीज में 2-0 से हराने के बाद पाकिस्तान चैंपियनशिप तालिका में 43.3 प्रतिशत अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रहेगा। साउथ अफ्रीका 30.0 प्रतिशत अंकों के साथ छठे स्थान पर खिसक गया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में ऐतिहासिक जीत के बाद वेस्टइंडीज 23.8 प्रतिशत अंकों के साथ सातवें स्थान पर है। बांग्लादेश की टीम अंतिम स्थान पर है जिसने अब तक कोई अंक हासिल नहीं किए हैं।

कोहली की कप्तानी में लगातार चौथा टेस्ट मैच हारा भारत

विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम लगातार चार टेस्ट मैच हार चुकी है। इससे पहले भारत को एडिलेड, क्राइस्टचर्च और वेलिंगटन मे भी हार का सामना करना पड़ा था। कोहली की कप्तानी में भारत पिछले वर्ष न्यूजीलैंड दौरे पर गया था, जहां उसे दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-2 से क्लीन स्वीप झेलना पड़ा था। इसके बाद हाल ही में संपन्न हुए ऑस्ट्रेलिया दौरे में एडिलेड में खेले गए पहले दिन-रात्रि टेस्ट में उसे आठ विकेट से पराजय मिली थी। हालांकि इसके बाद कोहली अपने पहले बच्चे के जन्म के स्वदेश लौट गए थे और उनकी अनुपस्थिति में अजिंक्य रहाणे ने टीम की कमान संभाली थी। रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया दौरे में तीन टेस्ट मुकाबलों में कप्तानी की थी जिसमें भारत ने मेलबर्न टेस्ट जीता जबकि सिडनी टेस्ट ड्रॉ रहा। इसके बाद ब्रिस्बेन में खेले गए अंतिम और चौथे मुकाबले में भारत को जीत मिली और उसने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था। इंग्लैंड के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए कोहली की टीम में वापसी हुई और भारत को उनकी कप्तानी में एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा।

एंडरसन ने सुबह के सत्र में तीन विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी

भारत ने सुबह जब भारतीय पारी को आगे बढ़ाया तो उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय बल्लेबाज संघर्ष कराएंगे और मैच को ड्रा कराने की कोशिश करेंगे लेकिन करिश्माई तेज गेंदबाज एंडरसन ने सुबह के सत्र में तीन विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। गिल ने 15 और पुजारा ने 12 रन से भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। भारत को पहला झटका जल्दी ही लग गया। पुजारा को लीच ने स्लिप में बेन स्टोक्स के हाथों कैच करा दिया। भारत का दूसरा विकेट 58 के स्कोर पर गिरा। पुजारा ने 38 गेंदों में एक चौके की मदद से 15 रन बनाए। गिल और विराट ने दूसरे विकेट के लिए 34 रन की साझेदारी की लेकिन एंडरसन ने एक खूबसूरत इनस्विंगर से गिल को बोल्ड कर दिया। गिल ने 83 गेंदों पर 50 रन में सात चौके और एक छक्का लगाया। गिल का विकेट 92 के स्कोर पर गिरा। रहाणे ने तीन गेंदों का सामना किया और एंडरसन ने एक और बेहतरीन इनस्विंगर से रहाणे का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया। रहाणे ने अपने डिफेंस में ज्यादा गैप छोड़ दिया था। रहाणे का खाता नहीं खुला और उनका विकेट 92 के स्कोर पर ही गिरा। भारत को पंत से काफी उम्मीदें थीं जो लगातार अच्छा खेल रहे थे और उन्होंने पहले पारी में 91 रन बनाये थे लेकिन एंडरसन की गेंद पर वह रुट को कैच थमा बैठे। पंत ने 19 गेंदों में दो चौकों की मदद से 11 रन बनाए और उनका विकेट 110 के स्कोर पर गिरा।

सचिन, सहवाग, लारा जैसे दिग्गज क्रिकेटर करेंगे मैदान पर वापसी

सड़क सुरक्षा विश्व श्रृंखला में लेंगे हिस्सा

मुंबई। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, ब्रायन लारा और मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गज क्रिकेटर अगले महीने दो से 21 मार्च तक रायपुर में खेले जाने वाले अनएकेडमी सड़क सुरक्षा विश्व श्रृंखला (रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज) टी20 से एक बार फिर मैदान पर वापसी करेंगे।

इसके पहले सत्र को चार मैचों के बाद कोविड-19 महामारी के कारण पिछले साल 11 मार्च को निलंबित कर दिया गया था। आयोजकों ने मंगलवार को घोषणा की कि शेष सभी मैच रायपुर में 65,000 दर्शकों की क्षमता वाले नवनिर्मित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सचिन तेंदुलकर, वीरेन्द्र सहवाग, ब्रायन लारा, ब्रेट ली, तिलकरत्ने दिलशान, मुथैया मुरलीधरन के साथ क्रिकेट खेलने वाले पांच देशों के कई और पूर्व दिग्गज इस वार्षिक टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में जादू बिखेरेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्टइंडीज और मेजबान भारत के पूर्व क्रिकेटर भाग लेंगे। इसका आयोजन देश में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा, चूंकि देश में क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रियता वाला खेल है और यहां क्रिकेटरों को आदर्श नायकों के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में इस लीग का उद्देश्य सड़कों पर अपने व्यवहार के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सड़क सुरक्षा विश्व श्रृंखला टी20 के दौरान रायपुर में दिग्गजों की मेजबानी करना गर्व और सम्मान की बात है।

कोरोना के कारण आयरलैंड ने रद्द किया जिम्बाब्वे का दौरा

नई दिल्ली। आयरलैंड की सीमित ओवरों की सीरीज के लिए इस साल अप्रैल में होने वाला जिम्बाब्वे दौरा कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। जिम्बाब्वे क्रिकेट और क्रिकेट आयरलैंड ने आपसी सहमति से कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए इस सीरीज को स्थगित करने का फैसला किया है।

आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच इस साल अप्रैल में तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की सीरीज होनी थी। आयरलैंड की टीम को सीमित ओवर की सीरीज के लिए 28 मार्च को हरारे के लिए रवाना होना था। हालांकि, यह वनडे सीरीज आईसीसी विश्वकप सुपर लीग का हिस्सा नहीं थी। क्रिकेट आयरलैंड के हाई परफॉरमेंस निदेशक रिचर्ड होल्ड्सवर्थ ने बयान जारी कर कहा, हम इस दौरे के स्थगित होने से दुखी हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो यह हमारे जिम्बाब्वे के समकक्ष की ओर से अप्रत्याशित घोषणा नहीं है। इस दौरे को कराने के लिए हम उनके प्रयासों की सराहना करते हैं। लेकिन खिलाड़ियों और सहायक स्टाफ की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। हम देख रहे हैं कि इस दौरे को भविष्य में कब आयोजित किया जा सकता है।